www.sanjanabharati.com

दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर से प्रकाशित। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व उत्तराखंड में प्रसारित

facebook.com/Sanjanabharati

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

संजना भारती

RNI No. : DELHIN/2016/70240

आपका भरोसा, हमारी ताकत

2 टैरिफ आर्थिक युद्ध नहीं, आत्मनिर्भर शांति...

3 राज्य-स्तरीय समीक्षा मीटिंग में सहकारी सभाओं के...

4 मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में...

वर्ष: 9 | अंक: 279 | दिल्ली, शनिवार, 2 अगस्त 2025 | पृष्ठ संख्या: 4 | मूल्य: 1 रुपया

संक्षिप्त समाचार

उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव नौ सितंबर को होगा: निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली (एजेन्सी)। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नौ सितंबर को होगा। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को यह घोषणा की। आयोग के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिसूचना सात अगस्त को जारी होगी और नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त होगी। आयोग ने कहा कि यदि मतदान की जरूरत हुई तो यह नौ सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन के प्रथम तल पर स्थित कक्ष संख्या एफ-101, वसुधा में होगा। उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। उपराष्ट्रपति पद 21 जुलाई को निवर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा त्यागपत्र देने के कारण रिक्त हो गया था। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यसभा महासचिव को निर्वाचन अधिकारी और राज्यसभा सचिवालय के दो अधिकारियों को सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के पात्र होते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के 543 सदस्य शामिल होते हैं। राज्यसभा में पांच और लोकसभा में एक सीट रिक्त है, जिससे निर्वाचक मंडल की प्रभावी संख्या 782 हो जाती है और जीतने वाले उम्मीदवार को 391 वोटों की आवश्यकता होगी, बशर्ते सभी पात्र मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आगामी चुनाव में सत्तारूढ़ राजग को बढ़त हासिल है।

कानपुर के पास मुजफ्फरपुर-साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतरी

कानपुर (एजेन्सी)। उत्तर प्रदेश के कानपुर और टूंडला के बीच शुक्रवार दोपहर मुजफ्फरपुर-साबरमती जनसाधारण एक्सप्रेस के दो डिब्बे पटरी से उतर गए। रेल मंत्रालय के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा, अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। एक ट्रॉली कोच सहित दो डिब्बे लूप लाइन पर पटरी से उतर गए। उन्होंने बताया कि इंजन के पांचवे और छठे डिब्बे शाम चार बजकर 20 मिनट पर भाऊपुर यार्ड में पटरी से उतर गए। मरम्मत का काम तुरंत शुरू कर दिया गया है और कानपुर से रेलवे अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। अधिकारी ने बताया कि उत्तर मध्य रेलवे जोन के महाप्रबंधक और मंडल रेल प्रबंधक भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं।

फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज पर संस्पेस अब भी बरकरार

नई दिल्ली (एजेन्सी)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को 2022 में दर्जी कन्हैया लाल की हत्या से जुड़ी फिल्म "उदयपुर फाइल्स" का पुनर्मूल्यांकन करने का आदेश दिया। न्यायालय ने यह सवाल उठाया कि क्या केंद्र अपने पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के तहत संपादन और कट का आदेश दे सकता है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि पुनर्मूल्यांकन 6 अगस्त तक पूरा किया जाए और मौजूदा कानूनी मानदंडों का पालन करने का आग्रह किया। अदालत का यह आदेश सरकार द्वारा यह कहने के बाद आया कि वह उस पिछले निर्देश को वापस लेगी जिसमें फिल्म को विशिष्ट कट के साथ रिलीज करने की अनुमति दी गई थी। न्यायालय ने सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, जो भारत में फिल्मों के प्रमाणन और रिलीज को नियंत्रित करता है, के तहत केंद्र के पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का पालन करने के महत्व पर जोर दिया।

संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं का मूल है और इसे संचार का माध्यम बनाने की आवश्यकता: मोहन भागवत

(एजेन्सी)।

नागपुर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को कहा कि संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं का मूल है और इसे संचार का माध्यम बनाने की आवश्यकता है। संस्कृत को घर-घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है। उन्होंने संस्कृत के संरक्षण और प्रचार-प्रसार की वकालत की और कहा कि यह ऐसी है जो हमारी भावनाओं (भाव) को विकसित करती है। उन्होंने कहा कि सभी को इस प्राचीन को जानना चाहिए।

नागपुर में कवि कुलगुरु कालीदास संस्कृत विश्वविद्यालय में एक भवन के उद्घाटन समारोह में भागवत ने कहा कि संस्कृत को समझने और उसमें संवाद करने की क्षमता रखने में अंतर होता है। उन्होंने कहा कि संस्कृत विश्वविद्यालय को सरकारी संरक्षण मिलेगा, लेकिन जनता का संरक्षण मिलना भी जरूरी है। भागवत ने कहा कि संस्कृत भारत की सभी भाषाओं की जननी है और इसे आगे बढ़ाने के लिए लोगों को अपने दैनिक जीवन में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आरएसएस प्रमुख ने कहा, हमें अपने दैनिक संवाद में इस को बोलना सीखना होगा। यह दैनिक संवाद की बननी चाहिए। मैंने यह सीखी है, लेकिन मैं इसे धाराप्रवाह नहीं बोल पाता। संस्कृत को हर घर तक पहुंचाने की जरूरत है और इस में संवाद जरूरी है। भागवत ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने और स्वबल प्रदर्शित करने की आवश्यकता पर सभी एकमत हैं, जिसके लिए हमें अपनी बुद्धि और ज्ञान का विकास करना होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की ताकत उसका स्वत्व है यानी कि आत्मनिर्भरता द्वारा स्वामित्व की भावना। उन्होंने कहा, स्वत्व कोई भौतिक चीज नहीं, बल्कि व्यक्तिगत है और यह के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि संस्कृत को जानना, देश को समझने के समान है। भागवत ने विश्वविद्यालय में अभिनव भारती अंतरराष्ट्रीय अकादमिक भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी समाज जहां वैश्विक बाजार की बात करते हैं, वहीं हम वैश्विक परिवार की बात करते हैं, जिसकी विशेषता वसुधैव कुटुम्बकम (विश्व एक परिवार है) की अवधारणा है।

उन्होंने कहा कि पश्चिमी लोगों ने वैश्विक बाजार का विचार विकसित किया था जो अब विफल हो चुका है। भागवत ने जी20 की अध्यक्षता के दौरान 2023 में भारत द्वारा जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के बारे में बात की और बताया कि इसका विषय वसुधैव कुटुम्बकम था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने भाषण में संस्कृत की समृद्ध विरासत पर प्रकाश डाला और के विकास के लिए अपनी सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।

'दिल्ली को कूड़े से आजादी' अभियान की प्रभावी शुरूआत: रेखा गुप्ता

यह अभियान स्वस्थ दिल्ली की ओर बढ़ने का संकल्प है: सीएम

एसबी संवाददाता

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली को स्वच्छ और कचरा मुक्त बनाने की दिशा में एक प्रभावी पहल शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान प्रारंभ किया। यह अभियान 31 अगस्त (पूरे एक माह) तक चलेगा। इसमें जन-भागीदारी सहित विभिन्न सरकारी निकाय मिलकर एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि स्वच्छता अभियान तब सफल होता है, जब हम खुद पहल करें। आज दिल्ली को साफ-सुथरा और सुंदर बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को दिल्ली में नई गति देने वाला जनांदोलन है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान की शुरूआत कश्मीरी गेट स्थित महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय परिसर से की। मुख्यमंत्री ने स्वयं झाड़ू लगाकर संदेश दिया कि ऐसे अभियानों में सभी का जुड़ना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने इस कार्यालय की बदहाल स्थिति पर चिंता जताई और कहा कि इसे सुधारने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएंगे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि नागरिक कर्तव्य है। और अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर दिल्ली को कूड़े से मुक्त करें। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज से शुरू हुए दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान के अंतर्गत पहला दिन सभी सरकारी कार्यालयों की सफाई को समर्पित किया गया है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि प्रभावी सफाई व स्वच्छता के लिए ई-वेस्ट और कबाड़ के निस्तारण की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि हम केवल सफाई तक सीमित न रहें, बल्कि कार्यस्थलों में भी इसे प्रभावी रूप से अपनाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का हर विभाग इस विशेष स्वच्छता अभियान में पूरी शक्ति और प्रतिबद्धता के साथ जुटा हुआ है। राजधानी का हर विधायक, हर पार्षद और हर सरकारी कर्मचारी इस परिवर्तन का जिम्मेदार भागीदार है। इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत दिल्ली की जनता है। हर दिल्लीवासी इस बदलाव का सक्रिय हिस्सा है। यह अभियान सरकारी प्रयास नहीं, बल्कि पूरे शहर की सामूहिक भागीदारी का प्रतीक है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान एक नई सोच, नई दिशा और एक स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ दिल्ली की ओर बढ़ने का संकल्प है। इस एक महीने में हम सभी मिलकर हर गली, हर मोहल्ले, हर बाजार और हर सार्वजनिक स्थल को साफ करेंगे, कूड़े को हटाएंगे, हरियाली बढ़ाएंगे और स्वच्छता को स्थायी आदत बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि यह अभियान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन को दिल्ली में नई गति देने वाला जन-आंदोलन है। इसका उद्देश्य न केवल कूड़ा-कचरा मुक्त भारत बनाना है, बल्कि स्वच्छता को जन-आंदोलन का रूप देना भी है।

मुख्यमंत्री के अनुसार पूरी दिल्ली मिलकर इसे जन-आंदोलन का रूप देगी। देश की राजधानी दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने में सफाई व स्वच्छता की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में होगा भव्य आयोजन

हरियाणा सरकार करेगी ऐतिहासिक गुरुबानी विरासत को जीवंत

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हिंद दी चादर सिख गुरु श्री तेग बहादुर जी का हरियाणा की धरती पर 26 ऐतिहासिक गुरुद्वारों में उनके चरण पड़े हैं। 25 नवंबर को उनके 350वें शहीदी दिवस को हरियाणा सरकार कुरुक्षेत्र में भव्य तरीके से मनाएगी। मुख्यमंत्री यहां श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में जानकारी दी गई कि इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए राज्य स्तरीय कार्य समिति तथा राज्य स्तरीय एक्जीक्यूटिव कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की बैठक आगामी 6 अगस्त को बुलाई गई है, जिसमें हरियाणा सरकार की ओर से दिए जाने वाले सहयोग के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कम से कम 5 ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन हो जो श्री गुरु तेग बहादुर से जुड़े हों। उनके नाम से पौधारोपण, मैराथन, बाइक रैली, लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाए। श्री गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाओं और धर्म की रक्षा के लिए उनकी शहादत का संदेश देने के लिए अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह से प्रदेश के अलग-अलग स्थानों से चार शोभायात्राएं निकाली जाएंगी, जिनका समापन 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में किया जाएगा।

बैठक में इस बात की भी जानकारी दी गई कि कार्यक्रम का एक लोगो भी तैयार किया जाएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पेज भी बनाया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, प्रधान सचिव अरूण कुमार गुप्ता, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, महानिदेशक के.एम. पांडुरंग, स्पेशल ऑफिसर (कम्युनिटी पुलिसिंग एंड आउटरीच) पंकज नैन, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग की अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) श्रीमती वर्षा खंगवाल, मुख्यमंत्री के ओएसडी डॉ. प्रभलीन सिंह व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

रेखा सरकार का रेलवे, डीडीए सहित सभी विभागों को निर्देश, एक भी झुग्गी न तोड़ी जाए

जरूरत हुई तो झुग्गी बस्तियों पर बनी पॉलिसी में बदलाव किया जाएगा: सीएम रेखा गुप्ता

एसबी संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी की झुग्गी बस्तियों को लेकर महत्वपूर्ण व निर्णायक फैसले लिए हैं। उन्होंने रेलवे, डीडीए सहित सभी सरकारी विभागों को निर्देश जारी किए हैं कि दिल्ली में कोई भी झुग्गी न हटाई जाए। अगर विकास कार्य आदि को लेकर झुग्गी हटाई भी जाती है, तो उन्हें पहले वैकल्पिक आवास दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राजधानी के बाहरी इलाकों में सालों पहले बने करीब 50 हजार मकानों को संवारकर उन्हें झुग्गी वालों को देने का निर्णय कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने दो निर्णय और लिए हैं। उनका कहना है कि जरूरत पड़ी तो सरकार झुग्गी बस्तियों पर बनी पॉलिसी में बदलाव करेगी और झुग्गी वालो का आवास बचाने के लिए कोर्ट भी जाएगी। मुख्यमंत्री का स्पष्ट मत है कि झुग्गी वालों का दर्द किसी हाल में अनदेखा नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि दिल्ली में बसी झुग्गियां देश की राजधानी का एक अनिवार्य अंग हैं। इनका दिल्ली में वर्षों से निवास हैं। विपक्षी पार्टी ने हमेशा से ही झुग्गी वालों को वोट बैंक की राजनिति में फंसाए रखा है, लेकिन हमारी सरकार उनको सही मायनों में दिल्ली का निवासी बनाने के लिए लगातार गंभीर प्रयास कर रही है। इस मसले पर विभिन्न विभागों के साथ लगातार बैठकें आयोजित की जा रही हैं और झुग्गी वालों को स्थायीत्व देने के लिए ठोस निर्णय लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार दिल्ली सरकार का स्पष्ट मत है कि अब राजधानी में कोई भी झुग्गी हटाई नहीं जाएगी। इसके लिए रेलवे, डीडीए सहित सभी संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर लिए गए हैं कि दिल्ली में कोई भी झुग्गी हटाई नहीं जाएगी। हमारी सरकार का स्पष्ट मत है कि अगर विकास कार्य या अन्य किसी मसले को लेकर झुग्गी हटेगी तो उसे पहले वैकल्पिक आवास मिलेगा। उन्होंने कहा कि झुग्गी वालों को बचाने के लिए अगर नियमों में बदलाव भी करना पड़ा तो सरकार उससे पीछे नहीं हटेगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हर्ष की बात यह है कि दिल्ली के बाहरी इलाकों में सालों पहले बने करीब 50 हजार फ्लैट्स को अब गरीबों को दिया जाएगा। इन जर्जर व खाली फ्लैट्स को कुछ साल पहले जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत बनाया गया था। लेकिन दुख की बात यह है कि गरीबों व झुग्गी बस्तियों के हितों का दावा करने वालीं दिल्ली की पूर्व सरकारों ने इनका आवंटन नहीं किया, जिसके चलते यह फ्लैट्स रहने लायक नहीं रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब इन फ्लैट्स को पीएमएवाई-यू (प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी) के अंतर्गत झुग्गी वालों का देने का निर्णय ले लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष बात यह है कि जेएनएनयूआरएम के तहत दिल्ली सरकार के दो विभाग ड्यूसिब व डीएसआईआईडीसी को करोड़ों रुपये दिए गए थे। लेकिन पिछली सरकारों ने इनका उपयोग ही नहीं किया, जिस कारण यह धनराशि (करीब 732 करोड़ रुपये) वापस केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (टङ्घल्लवअ) को वापस की जानी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इस राशि को जर्जर फ्लैट्स को संवारने पर रजामंदी दे दी है। मुख्यमंत्री के अनुसार अब यह हजारों फ्लेट्स गरीब झुग्गीवालों के आवास के लिए काम आएंगे।

भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल ने स्वर्गीय संजय वर्मा के परिवार के साथ दुख साझा किया

'संजय वर्मा ने कठोर परिश्रम से समाज में बड़ा मुकाम हासिल किया'

एसबी संवाददाता

अबोहर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज शहर के प्रसिद्ध व्यवसायी स्वर्गीय संजय वर्मा के निवास पर जाकर शोकसंतप्त परिवार से मुलाकात की और संवेदना प्रकट की।

मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल ने संजय वर्मा के भाई जगत वर्मा से मिलकर दुःख साझा किया। उन्होंने कहा कि यह न केवल परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है, बल्कि समाज के लिए भी एक गहरी हानि है, जिसने एक संकल्पशील, कर्मठ और प्रेरणादायी व्यक्तित्व को खो दिया है। दोनों नेताओं ने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को शांति और परिवार को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान हो।

दोनों नेताओं ने कहा कि वर्मा परिवार ने कठिन परिश्रम, समर्पण और दृढ़ प्रतिबद्धता के बल पर एक ऊँचा मुकाम हासिल किया है, जिसके कारण अबोहर शहर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि इस दुःखद घड़ी में पंजाब सरकार उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी है। भगवंत मान और केजरीवाल ने यह भी दोहराया कि राज्य सरकार जघन्य अपराधों के प्रति किसी प्रकार की नरमी नहीं बरतेगी और दोषियों को ऐसी सजा दिलवाई जाएगी जो समाज के लिए उदाहरण बनेगी।

दोनों नेताओं ने आगे बताया कि इस हत्या में शामिल दो गैंगस्टर पंजाब पुलिस के साथ मुठभेड़ में पहले ही मारे जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने परिवार को आश्वासन दिया कि इस घटना में पूर्ण न्याय दिया जाएगा और इस घिनौने अपराध में संलिप्त किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वर्मा परिवार सहित पंजाब के हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इसके लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इस अवसर पर संजय वर्मा के भाई जगत वर्मा ने इस मामले में पंजाब पुलिस द्वारा की गई तेज और निर्णायक कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। उन्होंने इस दुःख की घड़ी में साथ खड़े होने और अपराधियों के विरुद्ध मिसाली कार्रवाई कर न्याय दिलाने के लिए दोनों नेताओं का धन्यवाद किया। इस अवसर पर आप पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया भी उपस्थित थे।

सरकार एअर इंडिया को वापस ले: तिवारी

नई दिल्ली (एजेन्सी)। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने शुक्रवार को सरकार से आग्रह किया कि एअर इंडिया को टाटा समूह से वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि टाटा समूह ने एयरलाइन को बर्बाद कर दिया है और कभी राष्ट्रीय एयरलाइन रही इस एयरलाइन का निजीकरण एक त्रासदी साबित हुआ है। चंडीगढ़ से लोकसभा सदस्य तिवारी ने एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि चाय उगाने वाले और कार बनाने वाले लोग अब एअर इंडिया का संचालन रहे हैं। तिवारी ने कहा, भारत सरकार को एअर इंडिया को टाटा कंपनियों से वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने एयरलाइन को बर्बाद कर दिया है।

दिल्ली में भूकंप व औद्योगिक हादसों से निपटने की तैयारियों की जांच के लिए मॉक ड्रिल

(एजेन्सी)।

नई दिल्ली। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) राष्ट्रीय राजधानी में आपदाओं से निपटने में आपातकालीन सेवाओं और सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन करने के लिए शुक्रवार को एक विशाल मॉक ड्रिल का आयोजन किया। यह अभ्यास 11 जिलों के 55 स्थानों पर एक साथ किया गया, जिसमें कई एजेंसियों ने हिस्सा लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, इस मॉक ड्रिल की शुरूआत एक नकली भूकंप की स्थिति बनाकर की गई। इसके बाद औद्योगिक और परिवहन क्षेत्रों में रासायनिक रिसाव के परिदृश्य को शामिल किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया और समन्वय की तैयारियों की जांच करना था। अधिकारियों ने बताया कि यह अभ्यास दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में एक साथ किया गया। इस दौरान अग्निशमन सेवा, पुलिस और राजस्व विभाग सहित विभिन्न एजेंसियों के बड़ी संख्या में कर्मियों ने रमेश नगर मेट्रो स्टेशन, मदर इंटरनेशनल स्कूल और राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल जैसे स्थानों पर बचाव एवं राहत अभ्यास में भाग लिया। आरएमएल अस्पताल में भूकंप और औद्योगिक दुर्घटना की स्थिति में आपातकालीन प्रतिक्रिया स्थिति की तैयारियों का अभ्यास कराया गया। मदर इंटरनेशनल स्कूल में, भूकंप के संकेत मिलने पर गैस और बिजली कनेक्शन काटने तथा बचाव का अभ्यास कराया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने भारतीय सेना तथा दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों के सहयोग से अभ्यास सुरक्षा चक्र का आयोजन किया, जो एक फील्ड-लेवल मॉक ड्रिल के साथ समाप्त हुआ। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने एक बयान में कहा कि भूकंप और औद्योगिक रासायनिक आपदा की स्थिति में दिल्ली-एनसीआर की तैयारियों की जांच के लिए आयोजित इस मॉक ड्रिल के समन्वय की जिम्मेदारी उसकी प्रमुख एजेंसी के रूप में डीडीएमए निभा रहा है।

सम्पादकीय

भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ने वाले अब क्षमा मांगें

जब भगवा आतंकवाद जैसा शब्द जबरन गढ़ दिया गया था तब मैंने मेरी कांग्रेस मुक्त भारत की अवधारणा पुस्तक में लिखा था कि भगवा आतंकवाद जैसा कोई शब्द या टर्म हो ही नहीं सकता, यह एक अशब्द है जिसे हमें बोलचाल, लेखन व विमर्श से निकला फेंकना होगा। इस शब्द को मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंग, केंद्र में एकाधिक विभागों के मंत्री रहे पी. चिदंबरम, तत्कालीन गृहमंत्री सुशील शिंदे और कांग्रेस ने केवल मोहरा बनकर गढ़ा था। इस शब्द के पीछे वस्तुतः तो वामपंथी छुपे हुए हैं जो प्रेत बनकर वेताल यानि कांग्रेस की पीठ पर अब भी सवार है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में जब भोपाल से साध्वी प्रज्ञा जी के विरुद्ध दिग्विजय सिंह चुनाव में उतरे थे तब उन्होंने समूचे चुनाव को भगवा आतंकवाद को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव के मध्य समाचार पत्रों में मेरा एक आलेख भी प्रकाशित हुआ था, जिसका शीर्षक था-भगवा आतंकवाद शब्द की अंत्येष्टि का सटीक समय। इस चुनाव में जानता ने दिग्विजय सिंह को भगवा आतंकवाद जैसा शब्द गढ़ने का यथोचित दंड दे दिया था। इस चुनाव में कम्युनिस्ट नेता सीताराम येचुरी भी भोपाल के सुंदर तालाब के किनारे पर बैठकर हिंदुत्व को मछली समझकर जाल डालकर बैठे हुए दिखे थे। उन्होंने भोपाल के ताल में एक नया शाब्दिक विष उँडेला था- हिंदू तो सदा से हिंसक रहा है। अरे, दिग्विजय जी, येचुरी जी, सहित भगवा आतंकवाद शब्द के सभी कथित नेताओं सुनो; हिंदू सदा से सहिष्णु रहा है, इतना सहिष्णु कि कई अवसरों पर इसका भूगोल और इतिहास ही बदल गया और कई अवसरों पर इस हिंदू सहिष्णुता ने हिंदूत्व के कुछ अध्यायों का समापन ही करवा दिया। यदि ऐसा नहीं होता तो, बाबर हजार मील दूर से भारत में आकर हमारे देश के आराध्य श्रीराम की जन्मभूमि पर बने मंदिर को नेस्तनाबूद कर बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं कर पाता। और, न ही दुर्दांत मुस्लिम शासक तैमुरलंग दिल्ली से हरिद्वार के समूचे मार्ग में हिंदू नरमुंड बिछा पाता, हिंदू हिंसक होता तो बख्तियार खिलजी भारतीय ज्ञान के प्रतीक, नालंदा को यूं आग के हवाले न कर पाता, न ही औरंगजेब काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ पाता और न ही लाखों भारतीय मातृशक्ति को जौहर करने को मजबूर होना पड़ता। यदि हिंदू हिंसक होता तो गुरु गोविन्द सिंह के दोनों पुत्रों को जीवित दीवार में चुनकर मार डालने जैसी दुर्दांत घटना न हुई होती और न ही, मोहम्मद गजनवी श्रीकृष्ण जन्म स्थान को मथुरा में ध्वस्त कर कब्जा पाता। मालेगांव मामले में आए हुए निर्णय का मर्म यही है कि यदि हिंदू सहिष्णुता और उस पर हुए अत्याचारों का इतिहास और पढ़ना हो तो वे संत मतिदास को पढ़ लें, गुरु तेगबहादुर को पढ़ लें, जलियांवाला बाग पढ़ लें, भगतसिंह के बम फेंकने की मानवीय शैली पढ़ लें, भारत का धर्म आधारित विभाजन और उसके बाद यहां की भूमि पर मुस्लिमों की बसाहट व पाकिस्तान से हिन्दुओं का मारकाट भरा निर्वासन पढ़ लें, वे सोहरावरदी पढ़ लें, मोपला काण्ड पढ़ लें। और यदि पुराना इतिहास न पढ़ना हो भगवा आतंकवाद की माला जपने वाले नेताओं को हाल ही का रामसेतु विध्वंस भगवान राम को काल्पनिक कहने का शपथपत्र और ऐन दीवाली की रात्रि पूज्य शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी का तालिबानी आदेश पढ़ लेना चाहिए। इन घटनाओं सहित लाखों अन्य इतिहास सिद्ध घटनाओं ने यह ब्रह्मसत्य स्थापित किया है कि हिंदू हिंसक नहीं सहिष्णु रहा है, क्षमाशील रहा है, सर्वसमावेश को, सर्वस्पर्श को आतुर व उत्सुक समाज रहा है! मालेगांव के संदर्भ में कांग्रेसी नेताओं द्वारा यह भी कहा गया था कि आतंकवादी घटनाओं में मुस्लिमों से अधिक हिंदू सम्मिलित रहते हैं। 2008 के बाद, विशेषकर 26/11 के मुंबई हमले से ठीक पहले, मालेगांव केस को आधार बनाकर कम्युनिस्ट रिमोटेड कांग्रेस्टिस्टों ने एक ऐसा नैरेटिव खड़ा किया था कि भारत में आतंकवाद को हिंदू संगठन बढ़ा रहें हैं। लेकिन यह एक वैचारिक आगजनी वाला झूठ था-राजनीतिक लाभ के लिए रचा गया नैरेटिव, जिसकी कीमत निर्दोष हिंदुत्व के मासूम संतों, सैनिकों व नागरिकों ने चुकाई है। लेफ्ट-लिबरल मीडिया, कुछ स्वघोषित बुद्धिजीवी और वामपंथी इतिहासकारों ने इस नैरेटिव को खुलकर समर्थन दिया। प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल श्रीकांत पुरोहित, स्वामी असीमानंद जैसे लोग, जो राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े थे, उन्हें आतंकवादी की तरह पेश किया गया, मीडिया ट्रायल चला, और तथाकथित सेकुलर ताकतों ने उनकी छवि को नष्ट-भ्रष्ट करने के प्रयास किए। साध्वी प्रज्ञा जी ठाकुर को गंभीर स्थिति के कैंसर की स्थिति में भी कारावास में रखा गया, उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गईं।

जयंती

उमाकांत मालवीय

जन्मः 2 अगस्त, 1931; मृत्युः 11 नवम्बर, 1982) हिंदी के प्रतिष्ठित कवि एवं गीतकार थे। पौराणिक सन्दर्भों की आधुनिक व्याख्या करते हुए उन्होंने अनेकानेक मिथकीय कहानियां और ललित निबंधों की रचना की है। उनकी बच्चों पर लिखी पुस्तकें भी बेजोड़ हैं। कवि सम्मेलनों का संचालन भी बड़ी संजीदगी से किया करते थे।

पुण्यतिथि

रामकिंकर बैज

जन्म-26 मई, 1906; मृत्यु-2 अगस्त, 1980) भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के अग्रदूतों में उनकी गणना होती है। 'संभाल परिवार', 'मिल कॉल', 'महात्मा बुध', 'मिथुन', 'सुजात' व 'रविंद्र नाथ टैगोर का आवक्ष' (पोट्रेट) आदि उनके प्रमुख मूर्तिशिल्प हैं। अपने दृढ़ संकल्प से वह भारतीय कला के प्रतिष्ठित प्रारंभिक आधुनिक कलाकारों में से एक बने थे। भारतीय कला में उनके अतुल्य योगदान के लिए वर्ष 1970 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया।

कल मिलेंगे

राजू (अपनी पत्नी से)-मेरी लड़ाई हुई है, पड़ोस के आदमी के हाथ में जो आया उसने उससे मुझे पीट दिया...
पत्नी-तो तुम भी मार आते दो-चार, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं था क्या?
राजू-मेरे हाथ में उसकी बीवी का हाथ था बस...

संजना भारती दैनिक

भगवान शंकर जी के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक-**संजय कुमार** द्वारा आर.डी. प्रिंटर एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-41, सेक्टर-8, नोएडा, उत्तर प्रदेश से मुद्रित तथा ए-281सी, गली नं. 3, ए-ब्लॉक, अम्बिका विहार, शिव विहार, दिल्ली-110094 से प्रकाशित। इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी।
RNI No. : DELHIN/2016/70240
Phone No.: 9871221635
E-mail ID: sanjanabharati16@gmail.com
(किसी भी वाद-विवाद में न्याय क्षेत्र दिल्ली ही होगा।)

टैरिफ आर्थिक युद्ध नहीं, आत्मनिर्भर शांति का रास्ता बने

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आर्थिक चिंतन मूलतः आत्मनिर्भर भारत, विकास के साथ विश्वास, और समान साझेदारी के सिद्धांतों पर आधारित रहा है। वे वैश्विक मंच पर भारत को एक समानाधिकार संपन्न राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं, न कि किसी बड़े राष्ट्र की कृपा पर चलने वाली व्यवस्था के रूप में। जब डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ का प्रहार करते हैं, तो नरेंद्र मोदी की सोच विरोध नहीं, विकल्प पर आधारित होती है

-ललित गर्ग

जब किसी वैश्विक ताकत के शिखर पर बैठा नेता व्यापार को भी सौदेबाजी और दबाव नीति का औजार बना ले, तब यह न केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था को झकझोर देता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के आधारभूत सिद्धांतों को भी चुनौती देता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाकर ऐसा ही एक आर्थिक आघात पहुँचाया है। इस टैरिफ का लक्ष्य स्पष्ट है, भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा को बाधित करना और अमेरिकी वर्चस्व की पुनः स्थापना करना। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य एवं भारत की उभरती अर्थव्यवस्था में अमेरिका की ट्रंपीय दादागिरी, एवं टैरिफ का तात्कालिक और दीर्घकालिक प्रभाव कितना क्या असर दिखायेगी, यह भविष्य के गर्भ में हैं। लेकिन इस सन्दर्भ में भारत सरकार की दृढ़ता सराहनीय है। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है, दोनों का द्विपक्षीय व्यापार 2024 में 190 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। ट्रंप और मोदी ने इस आंकड़े को दोगुना से भी ज्यादा 500 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन उस लक्ष्य पर सवालिया निशान लग गए हैं। ऐसे में, भारतीय कंपनियों को बहुत संभलकर अपने लिए नए बाजार खोजने व बढ़ाने चाहिए।

भारत की अर्थव्यवस्था अब दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों ने भारत को उत्पादन और नवाचार का नया केंद्र बनाया है। भारत का टेक्सटाइल, स्टील, ऑटो पार्ट्स और आईटी सेवा क्षेत्र वैश्विक बाजार में निरंतर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका द्वारा टैरिफ थोपना भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा से उपजे भय का संकेत है। लेकिन यह निर्णय केवल व्यापारिक नहीं, बल्कि रणनीतिक भी है। ट्रंप प्रशासन हमेशा से ही व्यापार संतुलन के मुद्दे को राष्ट्रीय गौरव से जोड़कर देखता रहा है। अमेरिका फर्स्ट की नीति का मुख्य हथियार रहा है, दूसरों को पीछे धकेलकर अमेरिका को आगे लाना। यह एकतरफा सोच व्यापार के मूल्यों और साझेदारी की भावना को कमजोर करती है। व्यापार समझौते पर 1 अगस्त की समय सीमा तक दोनों देशों के बीच जारी बातचीत किसी नतीजे पर न पहुंचने का बड़ा कारण भारत का अमेरिका की शर्तों पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं होना रहा है। उसे आगे भी तैयार नहीं होना चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं कि भारत अमेरिका से ऐसा व्यापार समझौता कर ले, जो केवल उसके हित में हो। इस तरह के समझौते तो तभी हो पाते हैं, जब दोनों पक्षों के हित सधते हैं। भारत को अपने हितों की रक्षा के लिए अडिग रहना चाहिए और यह स्पष्ट करने में संकोच भी नहीं करना चाहिए कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुचित दबाव के आगे झुकने वाला नहीं। भारत को ट्रंप के मनमाने फैसलों से डरने की आवश्यकता इसलिए भी नहीं, क्योंकि वे अपने फैसलों से पीछे हटने और उन्हें पलटने के लिए जाने जाते हैं। उनके इस रवैये के कारण उनकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फजीहत भी हो रही है। उन्हें यह समझ आ जाए तो अच्छा कि आज का भारत पहले वाला भारत नहीं है और अमेरिका का भी प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा।

डोनाल्ड ट्रंप की नीति अक्सर दबाव डालो और झुकावो पर आधारित रही है। चीन, यूरोप, मैक्सिको के साथ भी ट्रंप की व्यापार नीति टकरावपूर्ण रही है। लेकिन भारत, ऐतिहासिक रूप से संतुलन साधने वाली कूटनीति में विश्वास करता रहा है। भारत ने कई बार वार्ता के माध्यम से समझौते की दिशा में पहल की, लेकिन ट्रंप की आक्रामक नीति और डीलमेकिंग की व्यक्तिगत शैली ने किसी संतुलन को बनने नहीं दिया। भारत पर लगाया गया 25 प्रतिशत टैरिफ न केवल आर्थिक रूप से अनुचित है, बल्कि यह उभरते राष्ट्रों के आत्मनिर्भर बनने के अधिकार का भी हनन है। यह नव-उपनिवेशवाद का नया रूप है, जहँ आर्थिक हथियारों से शक्तिशाली राष्ट्र, विकासशील देशों को नियंत्रित करना चाहते हैं। राष्ट्रपति ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने और जुमार्ना लगाने की जो घोषणा की, वह उनकी दबाव की राजनीति का ही हिस्सा है। इस राजनीति की पोल खुल चुकी है। अच्छा होगा कि इसे देश के विपक्षी दल भी समझें। इसलिए और भी समझें कि संसद में आपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कहा कि सैन्य कार्रवाई को स्थगित किए जाने के सिलसिले में विश्व के किसी भी नेता की कहीं कोई भूमिका नहीं। स्पष्ट है कि भारत-पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई को कथित तौर पर रोकने का ट्रंप का दावा फर्जी है। वास्तव में इसी कारण वे अपने इस थोथे दावे को बार-बार दोहरा रहे हैं।

आज का भारत न केवल एक विशाल बाजार है, बल्कि एक नवाचारशील शक्ति भी है। दुनिया की सबसे बड़ी युवा जनसंख्या, तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था, और विविधता से समृद्ध उत्पादन क्षमता भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर कर रही है। भारत अब ह्लनिर्भरताह्व की नीति से निकलकर ह्लआत्मनिर्भरताह्व की ओर बढ़ रहा है। ट्रंप के टैरिफ का प्रभाव सीमित और अस्थायी होगा, लेकिन भारत की आर्थिक विकास यात्रा दीर्घकालिक और दृढ़ है। भारत के लिए यह चुनौती अवसर में बदलने का समय है, नए बाजारों की तलाश, घरेलू उत्पादन को और सशक्त बनाना, और वैश्विक साझेदारियों को नए रूप में ढालना। ट्रंप की दादागिरी भारत को झुका नहीं सकती। बल्कि यह भारत को और मजबूत और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दे सकती है। यह समय है जब भारत को अपने उत्पादन, नवाचार, निर्यात और कूटनीति को और धार देने की आवश्यकता है। हमें यह समझना होगा कि शक्ति का उत्तर शक्ति से नहीं, दूरदृष्टि और नीति से दिया जाना चाहिए। ट्रंप का टैरिफ एक चुनौती है, लेकिन भारत की आत्मा में संघर्ष से जीतने का इतिहास है। हमने हर संकट को अवसर में बदला है, और इस बार भी हम यही करेंगे, न केवल अपनी अर्थव्यवस्था के लिए, बल्कि वैश्विक आर्थिक संतुलन के लिए भी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आर्थिक चिंतन मूलतः आत्मनिर्भर भारत, विकास के साथ विश्वास, और समान साझेदारी के सिद्धांतों पर आधारित रहा है। वे वैश्विक मंच पर भारत को एक समानाधिकार संपन्न राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं, न कि किसी बड़े राष्ट्र की कृपा पर चलने वाली व्यवस्था के रूप में। जब डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ का प्रहार करते हैं, तो नरेंद्र मोदी की सोच विरोध नहीं, विकल्प पर आधारित होती है। वे इस तरह के दबावों को एक नई दिशा में सोचने और घरेलू उत्पादन एवं वैश्विक विविधीकरण का अवसर मानते हैं। टैरिफ वार के उत्तर में मोदी की प्रतिक्रिया सकारात्मक ही होती हुई दिख रही है, वे ट्रंप के टैरिफ से प्रभावित क्षेत्रों जैसे स्टील, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल को सरकारी सब्सिडी, टैक्स रियायत और तकनीकी समर्थन के जरिए बल दे सकते हैं। अमेरिका के अतिरिक्त यूरोप, दक्षिण-पूर्व एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे नए बाजारों में भारत अपनी पकड़ को और मजबूत करते हुए इस टैरिफ से उत्पन्न संकट को संतुलित कर सकता है।

ट्रंप भारत को अपना मित्र मानते हैं। लेकिन यह कैसी मित्रता है, जिसमें ट्रंप को भारत के गरीबों, किसानों, मजदूरों की कोई चिंता नहीं है। लेकिन मोदी की विदेश नीति में भी अमेरिका के साथ मित्रता है, लेकिन आत्मगौरव की कीमत पर नहीं। वे संवाद और दृढ़ता-दोनों का प्रयोग करते हैं। दबाव की राजनीति से न तो भारत झुकेगा, न रुकेगा। ट्रंप का टैरिफ हो या कोई और वैश्विक चुनौती, मोदी का भारत हर संकट में अवसर खोजता है। मोदी की आर्थिक दृष्टि एवं नीतियां किसी बाहरी राष्ट्र के मनोनुकूल नहीं, बल्कि भारत की आवश्यकताओं, संभावनाओं और स्वाभिमान के अनुरूप गढ़ी गई है। जब वैश्विक महाशक्तियां टैरिफ के हथियार से डराने लगें, तो समझो कि भारत की प्रतिस्पर्धा ने उन्हें असहज कर दिया है। मोदी इसे चुनौती नहीं, पहचान मानते हैं। मोदी कहते हैं-लोकल को ग्लोबल बनाओ, और यही उनका उत्तर है हर टैरिफ, हर दबाव, हर चुनौती को। मोदी की अर्थनीति उद्यमशीलता को राष्ट्रनिर्माण से जोड़ती है। उनका आर्थिक चिंतन केवल विकास नहीं, बल्कि स्वराज्य आधारित समावेशी आर्थिक स्वतंत्रता है। ट्रंप के टैरिफ की चुनौती को वे उसी तरह लेते हैं जैसे उन्होंने कोविड या ग्लोबल मंदी की ली थी-साहस, दूरदर्शिता और आत्मनिर्भरता के साथ।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

आखिर अमेरिकी 'टेररिस्ट इकॉनमी' और इंडियन 'डेड इकॉनमी' जैसे आरोपों के अंतरराष्ट्रीय मायने क्या हैं? बारीकीपूर्वक समझिए

अमेरिका को यह समझना होगा कि भारत, ग्रेट ब्रिटेन नहीं है जिससे मित्रता कर अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर पीछे धकेल दिया जाए। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान अमेरिका ने ग्रेट ब्रिटेन के साथ यही तो किया। जहां इंग्लैंड की अंतरराष्ट्रीय दुनियादारी में तूती बोलती थी, वहीं द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अमेरिका की बोलने लगी। द्वितीय विश्वयुद्ध में अमेरिका- सोवियत संघ (रूस व उसके 14 पड़ोसी देश) साथ थे

-कमलेश पांडेय

जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और तेजी से मजबूत होती जा रही 'समाजवादी अर्थव्यवस्था' यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकॉनमी करार दिया है, तो एक भारतीय होने के नाते उनसे मेरा सीधा सवाल है कि आखिर उनकी अमेरिकी अर्थव्यवस्था क्या है- 'कैपिटलिस्ट इकॉनमी' या 'टेररिस्ट इकॉनमी!' मुझे पता है कि वो मेरे इस सवाल का जवाब नहीं देंगे, इसलिए आज उनकी डॉलर डिप्लोमेसी, मिलिट्री डिप्लोमेसी और घृणित कूटनीति को आईना दिखलाना अपना राष्ट्रधर्म/बुद्धिजीवी धर्म समझता हूं। वहीं, अमेरिका को यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि रूस के साथ भारत गर्त में नहीं, बल्कि उंस शिखर पर जाएगा जहां आज अमेरिका काबिज है!

सच कहूं तो सात समुंदर पार बसा अमेरिका यदि अपनी फूट डालो और राज करो वाली क्षुद्र नीतियों और अभद्र स्वभाव/व्यवहार के बल पर एशिया-यूरोप के देशों पर शासन करना चाहता है तो अब उसके दिन लद गए हैं। उसे ब्रिटिश भूलों से सबक सीखने की दरकार है, क्योंकि 'कूचरा की पारी अंतिम बारी' वाली भारतीय कहावत अब उस पर चरितार्थ होती दिखाई दे रही है। आज वह रूस, चीन, भारत, ईरान आदि सबकी आंखों पर चढ़ चुका है और उसका बचा-खुचा भ्रम बहुत जल्दी टूटने वाला है, जिसकी बौखलाहट उसके कदम दर कदम में दिखाई दे रही है।

भारत के प्रति उसका जो विद्वेष भरा रवैया है, शायद वही उसकी ताबूत की अंतिम कील बन जाए। वह पाकिस्तान को भड़काकर भारत को कमजोर नहीं कर सकता, बल्कि भारत यदि अपने पर आ गया तो एशिया-यूरोप से उसके पांव उखड़ते देर नहीं लगेंगे। क्योंकि रूस-चीन-उत्तरकोरिया-ईरान-इराक-सीरिया आदि उससे पहले से ही खार खाए बैठे हैं। जहां तक भारत-अमेरिका सम्बन्धों की बात है तो यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत-अमेरिका सम्बन्ध एक अस्वाभाविक दोस्ती है, जिसमें छल-प्रपंच की बू आती है। जबकि भारत-रूस सम्बन्ध एक स्वाभाविक मित्रता है, जो वक्त की कसौटी पर शत-प्रतिशत खरा उतरा है। कभी अमेरिका और सोवियत संघ, और अब अमेरिका व चीन, अमेरिका एवं रूस के पारस्परिक वैश्विक महत्वाकांक्षा भरे रिश्तों में गुटनिरपेक्ष देश भारत की अहमियत प्रारंभ से यही रही है कि उसका झुकाव जिधर होगा, उसका पलड़ा सदैव भारी होगा। लेकिन जहां रूस ने भारतीय गुटनिरपेक्षता को बेझिझक स्वीकार किया, वहीं अमेरिका द्वारा भारत को अपने पाले में खींचने और फिर स्वभाववश दगाबाजी करने की जो हड़बड़ाहट दिखाई जा रही है, इस आशय की डील अविलंब करने का जो वैश्विक दबाव बनाया जा रहा है और इसी प्रक्रिया में अमेरिकी वयोवृद्ध राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंफ द्वारा जो घिनौनी बयानबाजी की जा रही है, उससे भारत का बाल भी बांका होने वाला नहीं है।

यदि अमेरिका-चीन को भ्रम है कि वे पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, म्यांमार आदि को उकसा कर भारत की तरक्की की राह में रोड़े अटकायेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में अशांति फैलाकर हथियारों की बिक्री बढ़ाएंगे तो यह उनका दिवास्वप्न है। 'अमेरिकी आतंकवाद' और 'चीनी नक्सलवाद' से या इस्लामिक चरमपंथ से जितनी क्षति पहुंचाई जा सकती थी, वह पहुंचाई जा चुकी है। लेकिन अब पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह द्वारा जो चुन चुन कर हिसाब लिए जा रहे हैं, उससे अमेरिका-चीन की बौखलाहट भी समझने लायक है। जबकि पाकिस्तान प्रेमी अरब-एशियाई देशों द्वारा भारत के इस्लामीकरण की कोशिशें भी दम तोड़ चुकी हैं। ऐसे में जब भारत ऑपरेशन सिंदूर की तरह अगला पलटवार करेगा तो अमेरिका-चीन को भारतीय उपमहाद्वीप में मुंह छिपाने की जगह भी नहीं मिलेगी।

अमेरिका को यह समझना होगा कि भारत, ग्रेट ब्रिटेन नहीं है जिससे मित्रता कर अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर पीछे धकेल दिया जाए। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान अमेरिका ने ग्रेट ब्रिटेन के साथ यही तो किया। जहां इंग्लैंड की अंतरराष्ट्रीय दुनियादारी में तूती बोलती थी, वहीं द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अमेरिका की बोलने लगी। द्वितीय विश्वयुद्ध में अमेरिका- सोवियत संघ (रूस व उसके 14 पड़ोसी देश) साथ थे। लेकिन विश्वयुद्ध खत्म होते ही अमेरिका ने यूरोप को दो फाड़ कर दिया और इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे बड़े देशों को उसके खिलाफ कर दिया। फिर लंबे चले अमेरिका-सोवियत संघ शीत युद्ध के दौरान 1989 आते आते सोवियत संघ को भी छिन्न-भिन्न करवा दिया। हालांकि, तीन दशक बाद जब रूस ने अपने खोए हुए गौरव को प्राप्त कर लिया, तब उसे अमेरिका-यूरोप के नाटो देशों ने यूक्रेन में उलझा दिया, जिससे साढ़े तीन वर्षों से भीषण युद्ध जारी है।

वहीं, अपनी वैश्विक बादशाहत बनाए रखने के लिए अमेरिका ने एशिया महादेश में भी कई बड़े गेम खेले। उसने एशियाई अरब देशों के खिलाफ इजरायल को भड़काया और उसे अपना पूर्ण सहयोग दिया। भारत के खिलाफ पाकिस्तान को भरपूर समर्थन दिया। चीन-भारत के बीच तिब्बत मुद्दे को हवा दी। अफगानिस्तान में रूस का अवरोधक बनने के लिए तालिबान पैदा किया। कश्मीर हासिल करने के लिए आतंकवाद पैदा किया। इससे अमेरिकी हथियार व ड्रग्स कारोबार में भारी मुनाफा हुआ। लेकिन रूस के खिलाफ जिस चीन को अमेरिका ने प्रश्रय दिया, अब वही उसके लिए भष्मासुर बन चुका है। अमेरिकी शह पर मुस्लिम देश भी दो फाड़ हो चुके हैं।

यही वजह है कि अमेरिका विगत 25 वर्षों तक भारत को अपने पाले में खींचने के लिए ढेर सारे वैश्विक प्रयास किए। स्वभाव से विनम्र प्रधानमंत्री अटलबिहारी बाजपेयी और पीएम डॉ मनमोहन सिंह तो अमेरिकी चक्रब्युह में फंस गए, लेकिन स्वभाव से तेज तर्रार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी वैश्विक चालें चलीं कि अमेरिकी चतुराई की सारी हवा निकल गई। उन्होंने उसकी कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था, जिसे टेररिस्ट अर्थव्यवस्था भी समझा जाता है, की ऐसी बखिया उधेड़ी कि आज वह बाप-बाप चिल्ला रहा है। जी-7 के ऊपर ब्रिक्स को इतना कद्दावर बनवा दिया कि अमेरिका के पसीने छूट रहे हैं। उसे टेररिस्ट अर्थव्यवस्था इसलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान के सहारे दुनिया भर में आतंकवादी पैदा करने, उन्हें वित्तीय मदद देने और फिर उपजी अशांति का लाभ उठाकर अपनी कम्पनियों के हथियार खपाने व ड्रग्स के कारोबार को बढ़ाने का जो खुला खेल फरुखाबादी चलता रहा है, उसका मास्टरमाइंड देश अमेरिका ही है। उसी की छाप उसके अनुगामी चीन पर पड़ी है, जिससे वह ज्यादा परेशान है।

वहीं, पीएम मोदी इस बात को नहीं भूले हैं कि यह वही अमेरिका है जिसने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें अपना वीजा नहीं दिया था और उनके प्रधानमंत्री बनते ही उनकी आवभगत करने लगा। यही वजह है कि पीएम मोदी ने अमेरिका, रूस और चीन जैसे बड़े देशों से सिर्फ उतना ही संपर्क रखा, जितने में कि भारतीय हित सधता रहे। इसलिए उन्होंने "गिव एंड टेक डिप्लोमेसी" को तवज्जो दी। "बिटविन द लाइन्स" पर हमेशा अडिग रहे। इससे भारत ने आशातीत तरक्की की और आत्मनिर्भर हो गया। यही बात अमेरिका, रूस, चीन, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान आदि देशों को अखड़ने लगी।

हालांकि रूस-चीन का नेतृत्व तो शांत रहा, लेकिन अमेरिकी नेतृत्व अपनी खींझ छुपा नहीं पाया। अपने पहले कार्यकाल में भारत के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने वाले डॉनल्ड ट्रंफ ने अपने दूसरे कार्यकाल में दुश्मनी की भाषा समझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़े। ऐसा इसलिए कि आज अमेरिकी रुपया डॉलर और अमेरिकी सेना दोनों का भविष्य खतरे में है। जब रूस-चीनी गठजोड़ उनपर भारी पड़ने लगा तो उन्होंने न केवल अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुला ली, बल्कि युद्ध नहीं करने की भी दलीलें देने लगे। इससे साफ है कि दुनिया के विभिन्न देशों में जाकर युद्ध करते रहने का आदी बन चुका अमेरिका अब मजबूत पलटवार देखकर आर्थिक व सैन्य पैमाने पर थक चुका है।

खेल/विदेश/कारोबार/फिल्म

ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान समेत कई देशों में संघर्ष खत्म कराए, उन्हें नोबेल मिलना चाहिएः व्हाइट हाउस

(एजेन्सी)।

अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने दुनिया भर में कई संघर्षों को समाप्त कराया है, जिनमें भारत और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष भी शामिल है।

ट्रंप ने 10 मई को सोशल मीडिया पर यह घोषणा की थी कि भारत और पाकिस्तान ने वाशिंगटन की मध्यस्थता में एक रात तक चली बातचीत के बाद पूर्ण रूप से और तुरंत संघर्षविराम पर सहमति जतायी है। इसके बाद से वह बार-बार यह दावा करते रहे हैं कि उन्होंने दोनों देशों के बीच तनाव कम कराने में मदद की। लेविट ने बृहस्पतिवार को व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया, इजराइल और ईरान, रवांडा और लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, भारत और पाकिस्तान, सर्बिया और कोसोवो तथा मिस्र और इथियोपिया के बीच संघर्ष समाप्त कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने अपने छह महीने के कार्यकाल में औसतन हर महीने एक शांति समझौता या युद्धविराम कराया है। प्रेस सचिव ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने का वक्त आ गया है।

ट्रंप ने यह दावा करीब 30 बार दोहराया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम कराने में मदद कीह्व और परमाणु हथियार संपन्न दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों से कहा कि अगर वे संघर्ष रोकते हैं, तो अमेरिका उनके साथ बहुत ज्यादा व्यापार करेगा।

वहीं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस सप्ताह संसद में कहा कि किसी भी देश के किसी भी नेता ने भारत से ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा था। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को स्पष्ट रूप से कहा कि पाकिस्तान के साथ संघर्षविराम लाने में किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सैन्य कार्रवाई रोकने और व्यापार के बीच कोई लेना-देना नहीं था।

राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए जयशंकर ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले से लेकर 16 जून तक प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच टेलीफोन पर कोई बातचीत नहीं हुई थी।

इधर पहुंचे ट्रंप के दूत, उधर गाजा में भोजन तलाशते 91 लोगों पर बरसा दी गई गोलियां

(एजेन्सी)।

गाजा में मानवीय संकट गहराता जा रहा है, रिपोर्टों के अनुसार पिछले 24 घंटों में खाद्य वितरण केंद्रों तक पहुँचने की कोशिश करते हुए 91 फिलिस्तीनी मारे गए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इजराइली बलों पर मानवीय सहायता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे नागरिकों पर जानबूझकर गोली चलाने का आरोप लगाया है। जिकिम क्रॉसिंग पर यह दिल दहला देने वाली घटना ऐसे समय हुई है जब अमेरिका के मध्य-पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ युद्धविराम और बंधकों की रिहाई पर बात करने इजरायल पहुंचे हैं।

गाजा के शिफा अस्पताल और सिविल डिफेंस एजेंसी के अनुसार, ये लोग उस काफिले को रोकने की कोशिश कर रहे थे जो मानवीय सहायता लेकर उत्तरी गाजा के भंडारण केंद्रों की ओर बढ़ रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जैसे ही लोगों ने देखा कि कुछ लोग ट्रक से सामान लूट रहे हैं, भूखे लोग दौड़ पड़े, तभी इस्त्राइली सेना ने गोलीबारी कर दी। हालांकि, इस्त्राइली सेना ने सिर्फ 'चेतावनी के लिए गोली चलाने' की बात मानी है और कहा है कि उसे किसी मौत की जानकारी नहीं है।

इस बीच, अमेरिकी दूत विटकॉफ ने यरुशलम में प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात कर गाजा में मानवीय हालात पर चर्चा की। डॉनल्ड ट्रंप प्रशासन के तहत विटकॉफ लंबे समय से हमास और इस्त्राइल के बीच मध्यस्थता की कोशिशों में जुटे हैं। गाजा में करीब 22 महीने से जारी जंग में अब तक 60 हजार से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र समर्थित एजेंसियों ने चेताया है कि इलाके में अकाल की स्थिति बन रही है। नेतन्याहू ने इन रिपोर्टों को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया कहा है।

खालिद जमील बने भारतीय फुटबॉल टीम के नए कोच

(एजेन्सी)।

भारतीय फुटबॉल टीम का इंतजार खत्म हुआ.. और भारतीय फुटबॉल फेडरेशन ने टीम के नए कोच का ऐलान कर दिया है। दरअसल, कुवैत में जन्में खालिद जमील को भारतीय फुटबॉल टीम का नया कोच बनाया गया है। शुक्रवार को एआईएफएफ ने इसका ऐलान खुद किया। खालिद ने 2017 में आइजॉल फुटबॉल क्लब को आई-लीग खिताब दिलाया था। बता दें कि, 13 वर्षों में पहली बार किसी भारतीय को भारतीय फुटबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। पूर्व भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और वर्तमान में इंडियन सुपर लीग की टीम जमशेदपुर एफसी के मैनेजर 48 वर्षीय जमील को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की कार्यकारी समिति ने तीन सदस्यों की सूची में से चुना है। अन्य दो दावेदार भारत के पूर्व मुख्य कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन और स्टीफन टारकोविक थे। स्टीफन पहले स्लोवाकिया की राष्ट्रीय टीम के कोच थे। महान स्ट्राइकर आईएम विजयन की अध्यक्षता वाली एआईएफएफ की तकनीकी समिति ने कार्यकारी समिति के अंतिम निर्णय के लिए तीन उम्मीदवारों को चुना था। जमीन स्पेन के मनोलो मार्केज का स्थान लेंगे, जिन्होंने भारत के हालिया संघर्षों के बाद पिछले महीने एआईएफएफ से नाता तोड़ लिया था। राष्ट्रीय पुरुष टीम के मुख्य कोच के रूप में सेवा देने वाले अंतिम भारतीय सावियो मेडेइरा थे, जिन्होंने 2011 से 2012 तक ये पद संभाला था। वहीं खालिद जमील के लिए अपनी नई भूमिका में पहली चुनौती मध्य एशियाई फुटबॉल संघ नेशंस कप है। ये टूर्नामेंट 29 अगस्त से ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जाएगा।

अब भी 6,017 करोड़ रुपये मूल्य के 2,000 रुपये के नोट चलन में : आरबीआई

(एजेन्सी)।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 2,000 रुपये के नोट को चलन से हटाये जाने के दो साल से भी अधिक समय बाद 6,017 करोड़ रुपये मूल्य के ये नोट अब भी चलन में हैं। शुक्रवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। दो हजार रुपये के बैंक नोट वैध मुद्रा बने हुए हैं।

आरबीआई ने 19 मई, 2023 को 2,000 रुपये के बैंक नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि चलन में 2,000 रुपये के बैंक नोटों का कुल मूल्य 19 मई, 2023 को कारोबार की समाप्ति पर 3.56 लाख करोड़ रुपये था। यह 31 जुलाई, 2025 को कारोबार की समाप्ति पर घटकर 6,017 करोड़ रुपये रह गया है। इस प्रकार, 19 मई, 2023 तक चलन में रहे 2,000 रुपये के बैंक नोटों का 98.31 प्रतिशत वापस आ चुका है। दो हजार रुपये के बैंक नोट को बदलने की सुविधा 19 मई, 2023 से रिजर्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों में उपलब्ध है।

नौ अक्टूबर, 2023 से, रिजर्व बैंक के निर्गम कार्यालय भी व्यक्तियों/संस्थाओं से उनके बैंक खातों में जमा करने के लिए 2,000 रुपये के बैंक नोट स्वीकार कर रहे हैं। इसके अलावा, लोग देश के किसी भी डाकघर से भारतीय डाक के माध्यम से 2,000 रुपये के नोट अपने बैंक खातों में जमा कराने के लिए आरबीआई के किसी भी निर्गम कार्यालय को भेज रहे हैं। ये निर्गम कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नयी दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम में हैं।

केरल स्टोरी को राष्ट्रीय पुरस्कार भाजपा की नफरत का उदाहरण : वेणुगोपाल

(एजेन्सी)।

कांग्रेस नेता के. सी. वेणुगोपाल ने शुक्रवार को कहा कि फिल्म द केरल स्टोरी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना इस बात का एक उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) किस तरह नफरत को प्रायोजित करती है और बढ़ावा देती है। पार्टी महासचिव ने कहा, यह फिल्म कूड़ेदान में फेंक दिए जाने लायक है और यह एक घटिया एजेंडा फैलाती है तथा मेरे खूबसूरत राज्य केरल को बदनाम करती है। केरल के अलप्पुझा से सांसद ने कहा, इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना इस बात का सबसे शानदार उदाहरण है कि भाजपा सरकार किस तरह नफरत को प्रायोजित करती है और बढ़ावा देती है। उन्होंने कहा कि केरल अपने ही देश की सरकार से मिले इस अपमान को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन देश के हर जिले और ब्लॉक में तेज व समावेशी विकास सुनिश्चित करना-नायब सिंह सैनी

एसबी संवाददाता

चण्डीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन देश के हर जिले और ब्लॉक में तेज व समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। जो एक विशेष मिशन और जन आंदोलन है। यह मिशन हर नागरिक को सशक्त बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी जिला या ब्लॉक विकास के क्षेत्र में पिछे न रहे।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने यह बात आज हरियाणा निवास चण्डीगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय सम्पूर्णता अभियान सम्मान समारोह में आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए कही। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में वर्ष 2018 में आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम की शुरूआत हुई थी। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय सेवाएं और मूलभूत ढांचा जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है। यह व्यापक दृष्टिकोण है, जिसमें हम सब मिलकर एक मजबूत, समृद्ध और समतापूर्ण भारत का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान के परिणाम लोगों के सामने आने शुरू हो गए है। नीति आयोग द्वारा दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सभी को मिलकर शत प्रतिशत कार्य करना है। ताकि इस अभियान के और अच्छे परिणाम जमीन स्तर पर मिल सके। उन्होंने कहा कि नीति आयोग के द्वारा पिछले दिए गए बिंदुओं पर स्वामित्व बनाए रखना जरूरी है। इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री के सपनों और लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने का कार्य कर रहे है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आकांक्षी जिला व ब्लॉक कार्यक्रम के तहत नीति आयोग द्वारा दिए गए विभिन्न क्षेत्रों में लक्ष्य को पूरा करने के उपरांत उस कार्य की रिपोर्ट लेकर वेरिफिकेशन करवाई जाए। ताकि कार्यक्रम के तहत धरातल पर हुए कार्य के बारे में पूर्ण और सटीक जानकारी प्राप्त हो सकें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए इस अभियान के बाद आज मेवात में इसके सकारात्मक परिणाम मिल रहे है। उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को यह भी निर्देश दिया कि नीति आयोग द्वारा हर वर्ष जो लक्ष्य इन जिलों के ब्लॉक के लिए दिया जाता है उस लक्ष्य को समय पर शत प्रतिशत हासिल करना है। अच्छे कार्य के लिए उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई भी दी है।

श्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश देत हुए कहा कि इन जिलों में किसानों को बागवानी की तरफ बढ़ाया जाए और बागवानी के नए-नए विकल्प दिए जाए। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि सायॅल हेल्थ कार्ड का सरलीकरण कर किसानों को इसकी पूरी जानकारी दी जाए। उन्होंने कृषि विभाग के निदेशक को निर्देश दिए कि कृषि विभाग का सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया जाए। जिसमें प्रगतिशील किसानों या कृषि के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले किसानों के साक्षात्कार लेकर उनको सोशल मीडिया पर डालकर अन्य किसानों को जागरूक किया जाए। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरूआत प्रधानमंत्री द्वारा 2018 में पिछड़े और विकसित जिलों के बीच में संतुलित और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत, विभिन्न विकासात्मक मानदंडों के आधार पर, देश भर के 800 से अधिक जिलों में से 115 जिलों का चयन किया गया था। इस पहल को और मजबूत बनाने के लिए, बाद में इस योजना के अंतर्गत आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया, जिससे इन क्षेत्रों का समग्र विकास संभव हो सका।

इस दौरान जिला नूंह, चरखी दादरी, भिवानी और रेवाड़ी के जिला उपायुक्तों ने आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम के तहत किए गए कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस दौरान मंख्यमंत्री ने आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले 26 अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुधीर राजपाल, सूचना जनसम्पर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक श्री के.एम.पांडुरंग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

राज्य-स्तरीय समीक्षा मीटिंग में सहकारी सभाओं के पुर्नोद्धार के लिए रोडमैप किया तैयार

एसबी संवाददाता

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री, पंजाब के आदेशों पर सहकारी सभाएं, पंजाब के रजिस्ट्रार श्री गिरिश दयालन, आईएएस की अध्यक्षता में सहकारिता विभाग की राज्य-स्तरीय समीक्षा मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में मुख्य ऑडिटर सहकारी सभाएं, ज्वाइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार और राज्य भर के सीनियर अधिकारियों ने शिरकत की। इस मौके पर रजिस्ट्रार ने क्षेत्रीय स्तर के नतीजे हासिल करने के लिए समय- बद्ध, लक्षित कारगुजारी और व्यक्तिगत जवाबदेही की जरूरत पर जोर दिया। मीटिंग के दौरान यह भी ऐलान किया गया कि अब से हर महीने की पहली तारीख को अनिवार्य रूप से ऐसी समीक्षा मीटिंगें करवाई जाएंगी।

मीटिंग के दौरान की गई बड़ी पहलकदमी फील्ड अफसरों की तरफ से घाटे में जाने वाली या बुरी कारगुजारी वाली सहकारी सभाओं को गोद लेना था। इस नये ढांचे के अंतर्गत, सभी इंस्पेक्टरों को उनके तैनाती स्थान के नजदीक एक सोसायटी सौंपी जायेगी जिससे वह बिना सचिव वाली 800 सोसायटियों को गोद ले सकें और उनका समर्थन कर सकें। इसके इलावा, हरेक ज्वाइंट रजिस्ट्रार की तरफ से कम से कम एक सोसायटी गोद ली जायेगी जबकि डिप्टी रजिस्ट्रार की तरफ से दो और सहायक रजिस्ट्रार की तरफ से तीन सोसायटियों को गोद लिया जायेगा। अधिकारियों से उम्मीद की जायेगी कि वह अपनी गोद ली गई सोसायटियों की देख-रेख करेंगे, सहयोग देंगे और कारगुजारी की निगरानी को यकीनी बनाऐंगे। इस कदम का मकसद सीधी जिम्मेदारी स्थापित करना और जमीनी स्तर पर सुचारू सुधार यकीनी बनाना है।

पीएसीएस कम्प्यूटरीकरण की स्थिति की समीक्षा करते हुये रजिस्ट्रार ने रोजमर्रा की निगरानी के जरिये प्रोजैक्ट में तेजी लाने के निर्देश जारी किये। उन्होंने बताया कि पाँच अतिरिक्त रजिस्ट्रारों को जिलेवार निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है, जबकि अतिरिक्त रजिस्ट्रार (हैडक्वाटर) तालमेल की निगरानी करेंगे और साप्ताहिक प्रगति रिपोर्टें पेश करेंगे। जिला-स्तरीय नोडल अफसरों की नियुक्ति लाजिमी की गई है, और कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया में किसी भी विरोध या रुकावट के विरुद्ध सख़्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। रजिस्ट्रार ने कहा कि पारदर्शिता, कुशलता और वित्तीय अनुशासन को यकीनी बनाने के लिए सहकारी सभाओं का मुकम्मल डिजिटल परिवर्तन बेहद जरूरी है। मीटिंग में ऑडिट सम्बन्धी जवाबदेही को और मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। सभी फील्ड अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमाओं के अंदर आडिट निरीक्षण की 100 प्रतिशत पालना को यकीनी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। यह स्पष्ट तौर पर कहा गया कि आडिट संबंधी त्रुटियों को जायज ठहराने के लिए पोस्ट-फैकटो विशेष रिपोर्टें अब स्वीकार नहीं की जाएंगी। जिन अधिकारियों ने पहले जिन मामलों में त्रुटि रहित रिपोर्टें जारी की थीं और बाद में जहाँ धोखाधड़ी होने का पता लगा था, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। मीटिंग के दौरान बताया गया कि अर्ध-न्यायिक कार्यवाहियों और अदालती मामलों के लिए एक व्यापक समीक्षा तंत्र भी बनाया गया था। यह निर्देश दिया गया था कि आर्डर की सभी प्रमाणित कापियां घोषणा के सात दिनों के अंदर जारी की जानी चाहिएं और लम्बित मामलों की साप्ताहिक समीक्षा डिप्टी रजिस्ट्रारों द्वारा की जानी चाहिए। धोखाधड़ी के इरादे या अधिकार क्षेत्र में दखलअन्दाजी से पास किये गए हरेक आर्डर की प्रशासनिक स्तर पर जांच की जायेगी, और उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

रजिस्ट्रार ने पीएसीएस में स्टाफ की कमी के मुद्दे को भी उजागर किया और सचिव के पदों को तर्कसंगत बनाने के निर्देश दिए, जिसमें स्पष्ट साप्ताहिक समय-सारणी और आने-जाने के खर्चों की अदायगी के लिए प्रस्तावित सहायता शामिल हो। खाद इंडेंट भी पीएसीएस मैंबरशिप और जमीनी होलडिंग पर असली-समय के डेटा के आधार पर किये जाने हैं, जिसमें निष्पक्ष वितरण को यकीनी बनाने के लिए बंद पड़ीं सोसायटियों को औपचारिक तौर पर कार्यशील सोसायटियों के साथ जोड़ा जाना है। सभी डीआरज को एक हफ़्ते के अंदर पूरा जिला- स्तरीय डेटा जमा कराने का काम सौंपा गया है। व्यापक प्रशासनिक सुधारों के हिस्से के तौर पर रजिस्ट्रार ने समूचे पत्र व्यवहार के लिए ईआफिस और अधिकारित punjab.gov.in ईमेल खातों के अनिवार्य प्रयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कागजी दस्तावेज भेजने की रिवायत को घटाया जाये। सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन आती सहकारी सभाओं के साथ मासिक मीटिंगें करें और उचित ढंग से दर्ज की कार्यवाहियों को हैडक्वाटर जमा करवाएं।

अंतरराष्ट्रीय सहकारी साल के मद्देनजर रजिस्ट्रार ने सभी अधिकारियों की तरफ से सक्रिय और क्षेत्र-आधारित सम्मिलन की जरूरत पर जोर दिया जिससे यह यकीनी बनाया जा सके कि न केवल सहकारी सभाओं का अस्तित्व बरकरार रहे बल्कि इनका विस्तार हो सके और यह ग्रामीण विकास एवं अर्थव्यवस्था में अहम योगदान डालें। आगामी राज्य-स्तरीय समीक्षा मीटिंग 2 सितम्बर, 2025 को होगी।

सरहद पार से हथियारों की तस्करी के नैटवर्क का पर्दाफाश; अमृतसर से 7 पिस्तौलों समेत तीन व्यक्ति और एक नाबालिग गिरफ़्तार

एसबी संवाददाता

चंडीगढ़/अमृतसर। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए जारी मुहिम के दौरान बड़ी सफलता हासिल करते हुये अमृतसर कमिशनरेट पुलिस ने एक नाबालिग समेत चार गुर्गों को गिरफ़्तार करके सरहद पार से गैर-कानूनी हथियारों की तस्करी में शामिल दो अलग-अलग माड्यूलों का पर्दाफाश किया है और उनके कब्जे में से सात आधुनिक पिस्तौल बरामद किये हैं। यह जानकारी आज यहाँ डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।

गिरफ़्तार किये गए व्यक्तियों की पहचान गाँव भगवानपुरा, तरनतारन के सिकन्दरजीत सिंह (19); अंतरजामी कालोनी, अमृतसर के प्रदीप सिंह उर्फ बब्बल (43); न्यू शहीद उधम सिंह नगर, अमृतसर के जरनैल सिंह (34) के तौर पर हुई है। इसके साथ ही तरनतारन के रहने वाले एक 17 साला नाबालिग को भी गिरफ़्तार किया गया है। बरामद किये गए हथियारों में दो गलौक पिस्तौल., .30 बोर के चार स्टार पिस्तौल, एक .32 बोर पिस्तौल और छह जिंदा कारतूस शामिल हैं। हथियार बरामद करने के इलावा पुलिस टीमों ने उनका मोटरसाईकल भी बरामद किया है, जिसका प्रयोग वह खेप पहुँचाने के लिए कर रहे थे। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्राथमिक जांच से पता लगा है कि उक्त मुलजिम पाकिस्तान स्थित तस्करों के संपर्क में थे और अंतरराष्ट्रीय सरहद के पास से हथियारों की खेप हासिल करते हैं। उन्होंने कहा कि इन हथियारों का प्रयोग अंतर-गिरोह दुश्मनियों को भड़काने और क्षेत्र में शांति भंग करने के लिए किया जाना था।

डीजीपी ने कहा कि इस सम्बन्धी अगले-पिछले संबंधों का पता लगाने और हथियारों की तस्करी के इस समूचे नैटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए आगे जांच जारी है।

आपरेशन के विवरण सांझे करते हुये पुलिस कमिश्नर (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि प्राथमिक जांच से पता लगा है कि मुलजिम सिकंदर और 17 साला नाबालिग, पाकिस्तान आधारित तस्करों के संपर्क में थे। उनका घर अंतरराष्ट्रीय सरहद के नजदीक है और निर्धारित स्थानों से ड्रोन के द्वारा फेंकी खेपें प्राप्त करते थे। दूसरे माड्यूल के बारे जानकारी देते हुये पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मुलजिम प्रदीप और जरनैल मृतक रवनीत सिंह उर्फ सोनू मोटा, जिसकी जग्गू भगवानपुरिया गैंग के साथ दुश्मनी थी, के साथी हैं। उन्होंने कहा कि यह हथियार पाकिस्तानी तस्करों से प्राप्त किये गए आधुनिक पिस्तौल हैं और मृतक सोनू मोटा ने अपनी मौत से पहले उनको यह सौंपे थे। उन्होंने कहा कि इन हथियारों की बरामदगी से इलाके में बड़ी आपराधिक कार्यवाही को टालने में सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्धी आगामी जांच जारी है और आने वाले दिनों में और गिरफ़्तारियाँ होने की संभावना है।

इस सम्बन्धी दो अलग-अलग मामले- पुलिस थाना गेट हकीमा, अमृतसर में हथियार एक्ट की धारा 25(7) और 27 के अधीन एफआईआर नं. 187 तारीख 26. 07. 2025 और पुलिस थाना बी-डिविजन, अमृतसर में हथियार एक्ट की धारा 25 अधीन एफआईआर नं. 160 तारीख 29.07.2025 दर्ज किये गए हैं।

वोटर लिस्ट जारी, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं निर्वाचक अपना नाम

- विशेष शिविर के जरिए 01 सितंबर तक दाखिल किया जाएगा दावा-आपत्ति
- छूटे हुए पात्र फॉर्म 06 के जरिए बन सकते हैं निर्वाचक

एसबी ब्यूरो प्रमुख/मृगांक शेखर सिंह

जमुई। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता गहन पुनरीक्षण के बाद नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दिया है। शुक्रवार को मतदाता सूची के प्रारूप को जमुई जिला में भी जारी किया गया। इसे चुनाव आयोग के वोटर सर्विस पोर्टल पर भी अपलोड कर दिया गया है। आधिकारिक वेबसाइट से मतदाता ऑनलाइन भी वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। अगर उसमें कोई गलती है या नाम नहीं जोड़ा गया है तो उस पर शनिवार से दावा और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम श्री नवीन ने समाहरणालय के सभा कक्ष में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर प्रारूप निर्वाचक सूची के साथ साथ छूटे हुए निर्वाचकों की सूची उन्हें हस्तगत कराया। उन्होंने जिले के सभी ईआरओ, एईआरओ और बीएलओ को भी प्रारुप सूची सौंप दिए जाने की बात कही।

श्री नवीन ने कहा कि मतदाता ऑनलाइन भी वोटर लिस्ट ड्राफ्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/download-eroll?stateCode=S04 पर जाएं अपना जिला, विधानसभा क्षेत्र का नाम चुनें। Roll Type के सेक्शन में SIR Draft 2025 को चुनें। कैपचा भरें

नीचे की ओर दी गई सूची में अपने बूथ की भाग संख्या को चुनें फिर पीडीएफ डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करें। आपके भाग संख्या की वोटर लिस्ट पीडीएफ फाइल में डाउनलोड हो जाएगी, उसमें आप अपना और अपने परिवार के लोगों का नाम चेक कर सकते हैं।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि दो अगस्त से हर दिन जिला के सभी प्रखंड कार्यालयों और नगर निकायों में निर्वाचक सूची में छूटे हुए पात्र लोगों का नाम जोड़ने , अपात्र का नाम हटाने और स्थानांतरण या संशोधन के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यहां पात्र नागरिक फॉर्म 06 के साथ जरूरी दस्तावेज संलग्न कर निर्वाचक सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। वहीं फॉर्म 08 के माध्यम से स्थानांतरण या संशोधन का दावा कर सकते हैं। उन्होंने पहली सितंबर तक दावा आपत्ति दाखिल किए जाने की बात-बताते हुए कहा कि विशेष शिविर में सुरक्षा का खास प्रबंध किया जा रहा है। फोटोग्राफी के साथ वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। डीएम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से विशेष शिविर को सफल बनाए जाने का आग्रह करते हुए कहा कि कोई भी पात्र निर्वाचक छूटे नहीं इसका ख्याल किया जाना है और अपात्र का नाम हटाने के लिए भी नामित लोगों को सचेत करना है। जिलाधिकारी श्री नवीन ने जम्हूरियत को और ज्यादा सेहतमंद बनाने के लिए कारगर पहल किए जाने की अपील की।

डीडीसी सुभाष चंद्र मंडल, एडीएम रविकांत सिन्हा, डीसीएलआर सुजीत कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी मो. नजरूल हक, अवर निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. मेनका कुमारी, जेडीयू जिलाध्यक्ष शैलेंद्र महतों, राजद प्रतिनिधि मुरारी राम, रालोसपा के जिलाध्यक्ष रामाधीन पासवान आदि संबंधित जन बैठक में उपस्थित रहे।

भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की ओर से नशे के खिलाफ पाठ्यक्रम शुरू; 'नशे के खिलाफ जंग' के तहत स्कूलों में पढ़ाया जाएगा पाठ्यक्रम

एसबी संवाददाता

अरनिवाला (फाजिल्का)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक अनुकरणीय पहल के तहत आठ लाख छात्रों को नशे के खतरों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से 'नशे के खिलाफ जंग' के तहत स्कूली पाठ्यक्रम शुरू किया।

सभा को संबोधित करते हुए 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि पंजाब के इस सीमावर्ती जिले से नशे के खिलाफ जंग में एक नए अध्याय की शुरूआत हो रही है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ पंजाब की लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है और राज्य सरकार की 'युद्ध नशे के विरुद्ध' अभियान के तीसरे चरण के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए सभी सरकारी स्कूलों में विशेष पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस पाठ्यक्रम के माध्यम से इन कक्षाओं के आठ लाख छात्रों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाएगा और नशीले पदार्थों से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि इस कार्यक्रम में 3658 स्कूलों को शामिल किया जाएगा और छात्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस पाठ्यक्रम में 35 मिनट के सत्र शामिल हैं, जो 27 सप्ताह तक पखवाड़े के आधार पर आयोजित किए जाएंगे और इनमें वृत्तचित्र, प्रश्नोत्तरी, पोस्टर और विचार-विमर्श गतिविधियां शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि इन सत्रों में नशे से संबंधित मिथकों, नशे को ना कहने की रणनीतियों और सहपाठियों के दबाव को नकारने की तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

'आप' के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही नशे के खिलाफ जंग शुरू कर रखी है और इस पहल के तहत 15 हजार तस्करों को जेल में डाला गया है, उनकी संपत्तियां जब्त की गई हैं और एक हजार किलो से अधिक हेरोइन बरामद की गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अवैध कारोबार से बनाई गई तस्करों की संपत्ति को ध्वस्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कारोबार के सबसे कुख्यात सरगना को राज्य की ईमानदार सरकार ने सलाखों के पीछे डाला है।

'आप' के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि यह कितनी बड़ी त्रासदी है कि सभी राजनीतिक पार्टियां इस नशा कारोबारी के पक्ष में आ गई हैं, जिससे उनका घृणित चेहरा उजागर हुआ है। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक पार्टियां नशे के कारण राज्य की दुर्दशा पर तो चुप हैं, लेकिन नशे के सरगना का समर्थन कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 'नशा विरोधी यात्रा' 10 हजार से अधिक गांवों और वार्डों में पहुंच चुकी है और इसके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि प्रत्येक युवा की यह जिम्मेदारी है कि वह राज्य सरकार की इस अनूठी और महान पहल का समर्थन करे। उन्होंने कहा कि युवाओं को सहपाठियों के दबाव में नशे का पहली बार स्वाद लेने के लिए नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि यह उनके लिए घातक हो सकता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह हम सभी के लिए नशे के खिलाफ जंग में शामिल होने का सही समय है। उन्होंने कहा कि नशा छोड़ने वाले पीड़ितों के पुनर्वास की कोशिशें भी चल रही हैं ताकि वे फिर से अपने पैरों पर खड़े होकर सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जी सकें। 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई भी राज्य या देश नशे के खतरे से अछूता नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी राज्य नशे की जड़ें काटने के लिए ऐसी जागरूकता मुहिमें चलाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण रूप से पंजाब अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण अंतरराष्ट्रीय सीमा पर होने के नाते तस्करों के लिए रास्ता बन गया है।

'आप' के राष्ट्रीय संयोजक ने दृढ़ता से कहा कि पंजाब के लोगों ने एकजुट होकर अपने समाज को नशा मुक्त करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने तस्करों के खिलाफ सख्ती से शून्य सहनशीलता नीति अपनाई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि समाज को जहर देकर आलीशान घरों में विलासिता का आनंद लेने वाले तस्कर हमारे लोगों के असली दुश्मन हैं और राज्य सरकार इन्हें किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेगी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की अभूतपूर्व कोशिशों से सरकारी स्कूलों का कायाकल्प हुआ है। उन्होंने कहा कि अब छात्र निजी स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं, जिससे लोगों का भरोसा झलकता है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि नशे के खिलाफ इस तरह के कार्यक्रम नहीं होने चाहिए थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से पंजाब को ऐसी परिस्थितियों में फंसा दिया गया है, जिसके कारण यह कार्यक्रम जरूरी हो गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकारों ने पंजाब के माथे पर नशे का दाग लगा दिया। उन्होंने कहा कि राज्य का कार्यकाल संभालने के बाद हमें रणनीति बनाने में समय लगा और अब राज्य सरकार ने नशा छोड़ने वालों के इलाज के लिए नशा-मुक्ति केंद्र शुरू किए हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार इन युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए भी काम कर रही है ताकि वे सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जी सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ जंग पिछले 150 दिनों से जारी है और सैकड़ों पंचायतों ने प्रस्ताव पारित कर यह प्रण लिया है कि वे कभी भी नशा तस्करों का साथ नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ यह जंग अब जन आंदोलन में बदल गई है और इसके हिस्से के रूप में राज्य सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रम में नशा विरोधी शिक्षा को शामिल किया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि छात्रों को नशे के लक्षणों और खतरों से अवगत कराया जाएगा क्योंकि नशे का पहली बार उपयोग ही जिंदगी की बबार्दी की शुरूआत करता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वोट बैंक की राजनीति नहीं करती और स्कूली बच्चों की तो वोट भी नहीं होती, फिर भी हम उन्हें इस अभिशाप के खिलाफ जागरूक करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकारों ने नशे के कारोबार को संरक्षण देकर युवाओं को बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि ये नेता पार्टियां भी पहाड़ों में कारोबार करते थे और वहीं जमीने खरीदते थे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन नेताओं के बच्चे हथियारबंद गार्डों की सुरक्षा में स्कूल जाते थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इन नेताओं के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब मजीठिया को पकड़ा गया था, तब कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा सभी उनके समर्थन में आ गए। उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ नेता कहते थे कि वे मजीठिया को उसका कॉलर पकड़कर घसीटेंगे, लेकिन अब वे उसका समर्थन कर रहे हैं।

गुरमीत सिंह खुड्डियां ने 11 नव-नियुक्त कृषि विकास अफसरों को नियुक्ति पत्र सौंपे

एसबी संवाददाता

चंडीगढ़। पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने अपने दफ़्तर में कृषि विभाग में 11 नौजवानों को कृषि विकास अफसर (ए. डी. ओ.) के तौर पर नियुक्ति पत्र सौंपे। नव-नियुक्त ए. डी. ओज को बधाई देते हुए पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने उनको अपनी ड्यूटी लगन और ईमानदारी के साथ निभाते हुये राज्य के किसानों की बेहतरी और कृषि सैक्टर के विकास को नये राह पर लेजाने के लिए अथक मेहनत करने के लिए प्रेरित किया।

कैबिनेट मंत्री ने नव-नियुक्त अफसरों की जिम्मेदारियों की महत्ता पर जोर देते हुये पंजाब को एक खुशहाल कृषि राज्य बनाने के लिए किसानों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह यत्नशील रहने के लिए उत्साहित किया। कृषि विभाग की भर्ती मुहिम पर रौशनी डालते हुये स. खुड्डियां ने बताया कि इससे पहले 20 मई, 2025 को 184 कृषि विकास अफसरों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे। इन 11 नव- नियुक्त ए. डी. ओज की भर्ती से विभाग में भर्ती किये गए ए. डी. ओज की कुल संख्या अब 195 हो गई है। जिक्रयोग्य है कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा सत्ता संभालने से लेकर अब तक राज्य के नौजवानों को 55000 से अधिक सरकारी नौकरियाँ दीं गई हैं।

कृषि मंत्री ने कहा कि यह भर्ती विभाग के सामर्थ्य में विस्तार करेगी जिससे राज्य के किसानों को और ज्यादा प्रभावशाली और कुशल सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। कृषि और किसान कल्याण विभाग के प्रशासनिक सचिव डा. बसंत गर्ग ने नव-नियुक्त कृषि विकास अफसरों को बधाई दी और उनको अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी और लगन के साथ निभाने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर कृषि विभाग के डायरैक्टर जसवंत सिंह और विभाग के अन्य सीनियर अधिकारी भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक: हरियाणा विधानसभा सत्र 22 अगस्त से होगा आरंभ

एसबी संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि हरियाणा विधानसभा का आगामी सत्र 22 अगस्त से बुलाया जाएगा। सत्र की अवधि का निर्णय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी द्वारा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए अहम निर्णयों की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार द्वारा गरीबों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि गरीब को मजबूत एवं सशक्त बनाया जाए, जबकि कांग्रेस सरकारें सिर्फ "बड़े आदमियों" के लिए योजनाएं बनाती रही हैं।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के प्रति सरकार पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपराधियों से निपटने के लिए मौके पर उचित निर्णय लें।

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष सिर्फ दुष्प्रचार करने में माहिर है। उन्होंने कहा कि "कांग्रेस शासित राज्यों जैसे कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना की बात नहीं करते, केवल हरियाणा पर उंगली उठाते हैं।" मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के घोषणा पत्रों को "केवल चुनावी हथकंडा" बताया, जबकि भाजपा सरकार हर वादे को जमीन पर उतारने में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि सरकार बिना किसी

भेदभाव या क्षेत्रवाद के तीन गुना गति से विकास कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि लाडो लक्ष्मी योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना तैयार की जा रही है और इसके लिए शीघ्र पोर्टल भी जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। उन्होंने बताया कि 2 अगस्त को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की जाएगी, जिससे लाखों किसानों के खातों में सीधा पैसा पहुंचेगा।

इस अवसर पर सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक श्री के. एम. पांडुरंग, मीडिया सचिव श्री प्रवीन आत्रे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बिजली विभाग राजौंद में 'एक पेड़ मां के नाम' कार्यक्रम हुआ आयोजित

■ एसडीओ योगेश कुमार ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार राजौंद। बिजली विभाग राजौद परिसर में शुक्रवार को पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से "एक पेड़ मां के नाम" कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मातृ सम्मान के साथ-साथ प्रकृति की रक्षा को प्रोत्साहित करना रहा।

इस मौके पर मुख्य रूप से मौजूद उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम राजौंद के एसडीओ योगेश कुमार ने सभी नागरिकों, क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे पर्यावरण को बचाने के लिए एक-एक पौधा जरूर लगाएं और उसकी देखरेख करें। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि, "धरती को हरा-भरा बनाए रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जिस प्रकार हम अपनी मां की देखभाल करते हैं, उसी प्रकार हमें प्रकृति की, 'धरती मां' की सेवा करनी चाहिए।"

इस अभियान के अंतर्गत कई पौधे लगाए गए और सभी उपस्थितजनों ने संकल्प लिया कि वे अपने लगाए पौधों को एक परिवार के सदस्य की तरह पालेंगे। कार्यक्रम में जेई जगदीश कुमार, जेई साहब सिंह, जेई सतीश कुमार सहित प्रवीण कुमार, मुकेश कुमार, सुरेश ड्राइवर, सुनील कुमार, सुशील, धर्मपाल, शुभम सहित बिजली विभाग के अन्य कर्मचारी एवं नागरिक उपस्थित रहे। सभी

ने उत्साहपूर्वक पौधारोपण में भाग लिया।

"एक पेड़ मां के नाम" अभियान न केवल पर्यावरण को बचाने का संदेश देता है, बल्कि लोगों को भावनात्मक रूप से भी वृक्षों से जोड़ता है। कार्यक्रम का समापन सामूहिक वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान के साथ किया गया।

इस अवसर पर सभी ने यह भी आग्रह किया कि ऐसे कार्यक्रम गांव-गांव, स्कूलों और कार्यालयों में आयोजित किए जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ और हरित पृथ्वी मिल सके।

सामाजिक संस्थाएं जागरूकता फैलाने में बखूबी निभा रही है अपनी भागीदारी: डीसी प्रीति

विश्व फेफड़े कैंसर दिवस पर प्लास्टिक, स्मोकिंग और ड्रग्स का त्याग करने की अपील

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार कैथल। डीसी प्रीति ने कहा कि समाज में जागरूकता फैलाकर नई पीढ़ी को नई दिशा दिखाने के कार्य में हम सबकी भागीदारी आवश्यक है। हमें सबसे पहले स्वयं को जागरूक होना है तथा नागरिक दायित्वों को अच्छे से निभाना है। इसके बाद हमें अपने परिवार और आसपास के समुदाय को जागरूक करना है। सामाजिक संस्थाएं जागरूकता फैलाने में अपनी भागीदारी बखूबी निभा रही है, जोकि काफी सराहनीय है।

डीसी प्रीति शुक्रवार को लघु सचिवालय में लायंस क्लब कैथल सैंटर्ल द्वारा नशा मुक्त हरियाणा अभियान के तहत विश्व फेफड़े कैंसर दिवस के उपलक्ष में शिक्षा विभाग के सहयोग से आयोजित जागरूकता रैली का शुभारंभ करने उपरांत बोल रही थीं। इस जागरूकता रैली में प्लास्टिक, स्मोकिंग और ड्रग्स का त्याग करने के संदर्भ में शहर वासियों को जागरूक किया गया। इसमें राजकीय प्राइमरी स्कूल नंबर 4

तथा लीटल फ्लावर स्कूल के विद्यार्थी शामिल थे। यह जागरूकता रैली लघु सचिवालय से नए बस स्टैंड तथा कुरुक्षेत्र रोड पर पहुंची।

डीसी प्रीति ने कहा कि प्लास्टिक का उपयोग करना पर्यावरण के साथ-साथ स्वास्थ्य को काफी नुकसान पहुंचाता है। प्लास्टिक आसानी से नष्ट नहीं होता। प्लास्टिक के कण भोजन और पानी में मिलकर कैंसर, हार्मोन असंतुलन और अन्य बीमारियां फैलाते हैं।

हर प्रकार का प्लास्टिक रिसायकल नहीं किया जा सकता और अधिकतर प्लास्टिक कचरे के रूप में जमा होता है। प्लास्टिक बनाने और जलाने की प्रक्रिया में भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें निकलती है।

उन्होंने आमजन का आह्वान करते हुए कहा कि वे कपडे.या जूट के थैले, स्टील या कांच की बोतलें का उपयोग करें। इसी तरह से स्मोकिंग व ड्रग्स एक बुरी लत है और यह कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। इसलिए हमें इनसे दूर रहना है।

इस मौके पर संस्था के प्रधान प्रवेश बंसल, सचिव पुनीत शर्मा, राजेंद्र पठानिया, डॉ. धूप सिंह धनखड़, राकेश कौशिक व स्कूली विद्यार्थी मौजूद रहे।

फफड़ाना सरकारी स्कूल में एक पेड़ मां के नाम किया पौधारोपण

एसबी ब्यूरो प्रमुख/विजय गर्ग असन्ध। को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फफड़ाना में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत एक विशेष पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम विद्यालय के प्राचार्य पवन कुमार के कुशल मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।

इस अवसर पर विद्यार्थियों ने अपनी माताओं के नाम पर पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण और मातृत्व सम्मान का संदेश दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और अपनी माँ के प्रति प्रेम व कृतज्ञता की भावना को प्रोत्साहित करना था।

इस अवसर पर प्रधानाचार्य पवन कुमार, प्राध्यापक योगेंदर राणा, धर्मवीर, जयपाल दीक्षित व सुमेर मालिक व योगेश शास्त्री नें कहा कि हमें हर वर्ष पेड़ पौधे आवश्यक लगाने चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाया गया यह अभियान एक पेड़ मां के नाम आवश्यक लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वृक्ष बनने तक इनकी रक्षा भी करनी चहिये। हर वर्ष जून व जुलाई सावन माह हम

पर्यावरण वन मौहत्सव के रूप में मनाते हैं। जिसका उद्देश्य प्रकृति के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उसे संरक्षित करने के लिए लोगों को प्रेरित करना होता है। प्राध्यापिका अनुपमा, सुलोचना देवी अनामिका, पूनम आदि स्टाफ सदस्यों नें कहा कि अपने खेतों, घर के आस पास या जहाँ भी खाली स्थान उपलब्ध हो, स्थान के हिसाब से फलदार व छायादार पेड़ पौधे आवश्यक लगाने चाहिए।

इस अवसर पर आम, अमरुद, जामुन, निम्बू, आँवला, नीम सहित फलदार व औषधीय पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में विद्यालय के सभी शिक्षकगण सक्रिय रूप से शामिल रहे। प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

सरकारी बस व नीजि बसों का कम्पीटीशन यात्रियों पर भारी

राजौंद सीएचसी बस सैलटर पर नहीं रूकी सरकारी बस, घबराहट में चलती बस से कूदी छात्रा हुई घायल

■ चालक फरार, राहगीर ने घायल को पहुंचाया सीएचसी राजौंद

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार राजौंद। शुक्रवार को राजौंद सीएचसी बस सेल्टर पर एक दर्दनाक घटना सामने आई। जब सरकारी बस के चालक ने एक छात्रा को बस सेल्टर राजौंद पर नहीं उतारा, जिससे घबराकर छात्रा घबरा गई। छात्रा पूजा के पिता राममेहर ने बताया कि वे रोहेडा के रहने वाले हैं। उसकी बेटी पूजा असन्ध से नर्सिंग का कोर्स कर रही है। वह प्रतिदिन बेटी को रोहेड़ा से सुबह राजौंद छोड़ने आता है व दोपहर बाद उसे राजौंद के सरकारी अस्पताल के बस सेल्टर से ले कर रोहेडा घर ले जाता है। पिता ने बताया कि आज सरकारी बस का ड्राइवर जल्दी में था उसने सरकारी अस्पताल बस सेल्टर राजौंद के अड्डे पर बस नहीं रोकी तो गूगामाडी के पास घबराहट में छात्रा पूजा चलती बस से कूद गई। घटना के बाद बस चालक व परिचालक एक बार नीचे आए। छात्रा को हॉस्पिटल नहीं पहुंचा व कैथल की ओर बस दौड़ा ले गए। मौके पर पहुंचे युवक राहुल शर्मा राजौंद ने घायल छात्रा को अपनी बाइक से, बागड़ी लोहारन की मदद से तुरंत उठाकर प्राथमिक उपचार के लिए राजौंद के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। बाद में उसे बेहतर इलाज के लिए कैथल रैफर कर दिया गया।

घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। परिजनों के अनुसार, छात्रा कई बार चालक से बस रुकवाने की गुहार लगाती रही, लेकिन चालक ने अनसुना कर बस को कैथल की ओर दौड़ा दिया। घबराकर छात्रा को मजबूरी में चलती बस से कूदना पड़ा, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। मार्केट यूनियन राजौंद प्रधान भीम सिंह राणा ने बताया कि उन्होंने बस सेंटर पर बैठे यात्रियों से पता किया तो पता चला कि बस चालक ने यहां पर बस नहीं रोकी, ना

घायल छात्रा को उठा कर सीएससी राजौंद पहुंचाने वाला नेक दिल इंसान राहुल शर्मा. (छाया: एसबी)

घायल छात्रा को देखने पहुंचे मार्केट यूनियन प्रधान भीम सिंह राणा (छाया: एसबी)

किसी सवारी को चढ़ने दिया, ना किसी सवारी को उतारा। बस सेंटर के आसपास भारी कीचड़ भी जमा था। बस चालक की प्राइवेट बस वाले से दौड लगाने की प्रतियोगिता चल रही थी। जिसके चलते उसने यात्रियों की जान को जोखिम में डाल दिया।

युवक राहुल शर्मा की तत्परता की परिजनों ने सराहना की और उसका धन्यवाद किया। परिजनों ने कहा कि यदि वह युवक समय पर मदद न करता, तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। परिजनों ने मामले की शिकायत मुख्यमंत्री एवं हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज को भेजने की बात कही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी बसों के चालक प्राइवेट बसों से प्रतिस्पर्धा में जानबूझकर जल्दबाजी करते हैं। कई बार सवारियों की सुरक्षा की पूरी तरह अनदेखी की जाती है। ऐसे में न तो नियमों का पालन होता है और न ही यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित सीएचसी राजौंद पर तैनात डा. रोहित ने बताया कि प्राथमिक उपचार के बाद छात्रा को जिला सरकारी अस्पताल कैथल रेफर कर दिया गया है छात्रा को गंभीर चोटे आई बताई गई है।

राजौंद में नशा मुक्ति एवं स्वास्थ्य जांच शिविर हुआ आयोजित

■ 150 मरीजों की जांच कर, नशा छोड़ने वालों को दी गई निशुल्क दवाएं

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार राजौंद। राजौंद के महाराणा प्रताप चौक स्थित धर्मशाला में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रेणु चावला के निर्देशन एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. कीर्ति शर्मा की अध्यक्षता में नशा मुक्ति एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का सफल आयोजन किया गया। यह शिविर आमजन को नशे की बुरी लत से छुटकारा दिलाने व स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास रहा।

शिविर में कैथल नशा मुक्ति केंद्र से पहुंची टीम ने नशे के आदी व्यक्तियों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया और नशा छोड़ने की इच्छा रखने वाले लोगों को मुफ्त दवाएं प्रदान की। इसके साथ लगभग 150 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें उच्च रक्तचाप और मधुमेह के मरीजों की पहचान कर उन्हें भी निःशुल्क दवाएं दी गईं।

नशा मुक्ति टीम में डॉ. सीमा, एटी ए एफ काउंसलर शीतल तथा सामाजिक कार्यकर्ता पंकज शामिल रहे। वहीं स्वास्थ्य जांच टीम में डॉ. जितेन्द्र मेहरा, डॉ. फरमान अली, डॉ. रमेश, डॉ. आशा, एएनएम बीना, दर्शना, सुनीता, रजनी, स्वास्थ्य निरीक्षक जितेन्द्र सिंह, स्वास्थ्य कार्यकर्ता रामनिवास, विनोद एवं आशा वर्कर्स सहित अन्य ने अपनी सेवाएं दीं। इस अवसर पर डॉ. कीर्ति कुमार शर्मा ने कहा,"हरियाणा सरकार का उद्देश्य है कि राज्य को पूरी तरह से नशामुक्त किया जाए। साथ ही, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसे रोगों से पीड़ित लोगों को मुफ्त दवाएं देकर उनका समुचित इलाज सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है।"

राजौद के स्थानीय, क्षेत्रीय नागरिकों ने शिविर का भरपूर लाभ उठाया। नागरिकों ने सरकार व प्रशासन का इस? यह शिविर लगाने के लिए धन्यवाद किया है। नागरिकों, दुकानदारों, मार्केट यूनियन राजौंद ने सरकार व प्रशासन से अनुरोध किया कि भविष्य में भी इस प्रकार के शिविर का आयोजन लगातार किया जाना चाहिए।

सीआईएसएफ यूनिट लाइन, पंजाब एवं हरियाणा सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ में 'जवान चौपाल' का उद्घाटन

एसबी संवाददाता

चंडीगढ़। सैनिकों के कल्याण को बढ़ाने और तनावमुक्त पारस्परिक जुड़ाव को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय कदम के रूप में, आज सीआईएसएफ यूनिट लाइन, पंजाब एवं हरियाणा सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ में 'जवान चौपाल' नामक एक नई पहल का उद्घाटन किया गया।

उद्घाटन समारोह में सभी रैंकों के सीआईएसएफ कर्मियों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। उल्लेखनीय है कि उद्घाटन समारोह का रिबन पिछले महीने सेवानिवृत्त हुए कर्मियों द्वारा औपचारिक रूप से काटा गया, जो सेवा की पीढ़ियों के बीच एकता के बंधन का प्रतीक है।

सीआईएसएफ वेट कैंटीन के निकट रणनीतिक रूप से स्थित, जवान चौपाल को एक अनौपचारिक, समुदाय-अनुकूल स्थान के रूप में डिजाइन किया गया है

जहाँ कर्मी जन्मदिन, अनौपचारिक चर्चा और विश्राम जैसे छोटे समारोहों के लिए एकत्र हो सकते हैं। "चौपाल" की सदियों पुरानी भारतीय परंपरा पर आधारित-एक ग्रामीण बैठक स्थल जो खुले संवाद को बढ़ावा देता है-यह पहल सुरक्षा बलों के भीतर उस भावना को पुनर्जीवित करने का प्रयास करती है। यूनिट के कई कर्मियों ने जवानों के बीच सौहार्द, तनाव मुक्ति और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में इस तरह के अनौपचारिक आयोजनों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि आज की तेज-तर्रार, डिजिटल जीवनशैली में, सार्थक मानवीय जुड़ाव अक्सर खो जाता है, जिससे तनाव और अलगाव का स्तर बढ़ जाता है। उन्होंने कहा, "जवान चौपाल न केवल एक सामाजिक केंद्र के रूप में कार्य करेगा, बल्कि सीआईएसएफ के तनाव प्रबंधन कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी होगा।" यह पहल सीआईएसएफ यूनिट पी एंड एचसीएस चंडीगढ़ के अपने कर्मियों के समग्र कल्याण को सुनिश्चित करने के निरंतर प्रयासों को रेखांकित करती है, चाहे वे ड्यूटी पर हों या ड्यूटी से बाहर।

हरियाणा कैबिनेट ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 में संशोधन को दी मंजूरी

एसबी ब्यूरो प्रमुख/विजेश कुमार चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सिख गुरुद्वारों के प्रबंधन से जुड़े कानूनी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इन संशोधनों का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, न्यायिक निगरानी सुनिश्चित करना और गुरुद्वारा संपत्तियों की घोषणा एवं प्रशासन के लिए स्पष्ट संरचना उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त धारा 44 और 45 को प्रतिस्थापित करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि मतदाता पात्रता, अयोग्यता, गुरुद्वारा कर्मचारियों से संबंधित सेवा मामलों और समिति सदस्यों की नियुक्ति से जुड़े विवाद अब विशेष रूप से नवगठित न्यायिक आयोग द्वारा सुलझाए जाएंगे। आयोग के आदेशों के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, जिसमें परिसीमा अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। इसकी भूमिका को और सुदृढ़ करते हुए, धारा 46 को संशोधित किया गया है ताकि आयोग को गुरुद्वारा संपत्ति, निधि और आंतरिक विवादों से संबंधित विवादों का निपटारा करने का अधिकार मिल सके। आयोग कदाचार के आधार पर समिति के सदस्यों को हटाने या निलंबित करने का अधिकार होगा, और वह गुरुद्वारा संपत्ति या निधि के दुरुपयोग या संभावित क्षति से संबंधित मामलों में स्वतः संज्ञान ले सकता है।

वह ऐसी परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा भी जारी कर सकेगा। इसकी विस्तारित भूमिका को समर्थन प्रदान करने के लिए, 46A से 46ठ तक नई धाराएं जोड़ी गई हैं।